5568

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

IA No.372 of 2024

IN

ORIGINAL APPLICATION NO.515 OF 2023

IN THE MATTER OF:

GANGA POLLUTION ..... **APPLICANT**

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS. .... **RESPONDENTS**

INDEX

Sl. No.	Particulars	Pages
1.	Reply on behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board.	
2	**Annexure-1** Copy of the inspection Report	

NEW DELHI
DATED: 05.02.2024

(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)
Counsel for U.P. Pollution Control Board
138, New Lawyers Chamber,
Supreme Court of India,
New Delhi-110001
(M.) 9810252518
Email: pradeepmisra@yahoo.com

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

I.A. No. 372 of 2024
IN
ORIGINAL APPLICATION NO. 515 OF 2023

IN THE MATTER OF:
GANGA POLLUTION .....APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS. .....RESPONDENTS

RESPONSE ON BEHALF OF U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

I,Dr. S.C. Shukla, S/.Late Shri Raj Nath Shukla, aged about 59 years, Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Prayagraj, U.P. do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That I in the above noted capacity am well conversant with the facts and record of the present case, hence am competent to swear this affidavit.

2. That the above noted Interim Application came up for hearing on 12.01.2024 when following order was passed:

> "...8. IA No. 372/2024 has been filed by Respondent NO. 26 seeking a direction permitting it to continue the construction of the

project. The reply to the said IA has been filed by the CSIR-Neeri, CPCB, the Prayagraj Development Authority and NMCG. Learned Counsel for the UPPCB submits that he will file the reply to the IA within two weeks 6 positively. It will be open to all other Respondents to file reply to the IA within the same period and the Applicant may file the rejoinder, if require, within two weeks thereafter...."

3. That in pursuance of the above order present response is being filed on behalf of UPPCB.

4. That the Regional Office of U.P. Pollution Control Board on 28.01.2025 made a site inspection of the project of M/s. Omaxe Pancham Realcon Pvt. Ltd., the Applicant in the above interim application. A copy of inspection report is being enclosed as **Annexure-A** with this affidavit.

5. That the Deponent craves leave of this Hon'ble Tribunal to treat the said inspection report as part and parcel of the instant response and the same will be referred and relied to at the time of hearing.

NOTARY R. K. OJHA Advocate Notary H.Q. All. GOVT. OF U.P.

4-2-25

DEPONENT

VERIFICATION:

I, the abovenamed deponent, do hereby verify that the contents of above affidavit are true to my knowledge derived from official record. No part of the same is false and nothing has been concealed therefrom.

VERIFIED ON THIS THE 04th DAY OF FEBRUARY, 2025 AT PRAYAGRAJ, U.P.

DEPONENT

NOTARY
R.C. OJHA
Advocate Notary
H.Q. Alld.
Reg No. 20120901
Date 2-2-2028
GOVT. OF U.P.
4-2-25

R. C. Ojha
Advocate Notary
Distt. Head Quarter
Allahabad 4-2-25

This document ... before me
of .... Dr. S.C. ...
Place at Allahabad the document is /are
identified by Shri........ ....
Advocate the Contents of the document
has been explained to the executed was
admit the to be Correct
and the documents ... attested ...

Umesh Chandra Ojha
Advocate Notary
Distt. Head Quarter 4-2-25

Annexure-A

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0 515/2023 (इन आई0ए0 नं0 372/2024) गंगा पाल्यूशन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में दिनांक 12.11.2024 को पारित आदेश के सन्दर्भ में आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0 515/2023 (इन आई0ए0 नं0 372/2024) गंगा पाल्यूशन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में दिनांक 12.11.2024 को आदेश पारित किया गया है, जिसके मुख्य अंश निम्नवत् है :–

".....8. IA No. 372/2024 has been filed by Respondent No. 26 seeking a direction permitting it to continue the construction of the project. The reply to the said IA has been filed by the CSIR-NEERI, CPCB, the Prayagraj Development Authority and NMCG. Learned Counsel for the UPPCB submits that he will file the reply to the IA within two weeks 6 positively. It will be open to all other respondents to file reply to the IA within the same period and the Applicant may file the rejoinder, if require, within two weeks thereafter....."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0 515/2023 (इन आई0ए0 नं0 372/2024) गंगा पाल्यूशन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में दिनांक 12.11.2024 को पारित आदेश के क्रम में मेसर्स पंचम रियलकॉन प्रा0लि0, (मेसर्स ओमेक्स लि0), ग्राम–देवरख उपरहार, देवरख कछार, चक विश्वनाथ, चकतेजुदिशी, मवई उपरहार, मढावन उपरहार एवं लवायनकलां तहसील–करछना, जनपद–प्रयागराज का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 28.01.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री तरूण शर्मा, डिप्टी जनरल मैंनेजर (लीगल), एवं श्री हर्ष प्रताप सिंह, सीनियर एक्जीक्यूटिव उपस्थित थे। विस्तृत आख्या निम्नवत् हैः–

1. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1,उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र सं0 3189/आठ–1–07–34/विविध/03, दिनांक 16.08.2007 के द्वारा उत्तर प्रदेश में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से हाईटेक टाउनशिप के विकास हेतु हाईटेक टाउनशिप नीति–2007 बनायी गयी है। प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, उ0प्र शासन लखनऊ के पत्र सं0 2608(2)/8–3–08–13विविध/08, दिनांक 03.07.2009 के द्वारा मेसर्स पंचम रियलकॉन प्रा0लि0 को हाईटेक टाउनशिप नीति–2007 के अन्तर्गत जनपद–प्रयागराज में 1535.17 एकड़ क्षेत्रफल में हाईटेक टाउनशिप विकसित किये जाने हेतु चयनित किया गया **(संलग्नक–01)।**

2. मेसर्स पंचम रियलकॉन प्रा0लि0, ग्राम–देवरख उपरहार, ग्राम–देवरख उपरहार, देवरख कछार, चक विश्वनाथ, चकतेजुदिशी, मवई उपरहार, मढावन उपरहार एवं लवायनकलां तहसील–करछना, जनपद–प्रयागराज द्वारा संशोधित कन्सेप्चुअल डी0पी0आर0 को नगर नियोजक, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज के पत्र सं0 598/हाईटेक टाउनशिप/नगर नियोजक/वि0प्रा0/2009, दिनांक 24.10.2009 के द्वारा अनुमोदित किया गया है **(संलग्नक–02)।**

3. राज्य स्तरीय पर्यावरण अधिप्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण, उ0प्र0 के पत्र सं0 226/एस0ई0ए0सी0/358/2009/टी0ए0 (जे), दिनांक 10.02.2010 के द्वारा मेसर्स पंचम रियलकॉन प्रा0लि0 द्वारा ग्राम–देवरख उपरहार, देवरख कछार, चक विश्वनाथ, चकतेजुदिशी, मवई उपरहार, मढावन उपरहार एवं लवायनकलां तहसील–करछना, जनपद–प्रयागराज में हाईटेक टाउनशिप विकसित

किये जाने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत किया गया है **(संलग्नक–03)।** एस0ई0आई0ए0ए0 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुसार हाईटेक टाउनशिप का कुल प्लाट एरिया 1535.12 एकड़ एवं टोटल बिल्टअप एरिया 8537950.52 वर्ग मीटर है। एरिया डिस्ट्रीब्यूशन का विवरण निम्नवत् है :–

Plotted	: 1039840.00 sq.mt.
Group Housing	: 1373632.39 sq.mt.
Commercial	: 413158.23 sq.mt.
Public/ Semi Public	: 540517.32 sq.mt.
Industrial	: 505713.12 sq.mt.
Recreational	: 220966.2 sq.mt.

4. मेसर्स पंचम रियलकॉन प्रा0लि0, (मेसर्स ओमेक्स लि0), ग्राम–देवरख उपरहार, देवरख कछार, चक विश्वनाथ, चकतेजुदिशी, मवई उपरहार, मढावन उपरहार एवं लवायनकलां तहसील–करछना, जनपद–प्रयागराज को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या पत्र सं0 एफ66176/सी–3/एन0ओ0सी0/3556/2010, दिनांक 05.05.2010 के द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत पर्यावरणीय प्रदूषण से सशर्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया **(संलग्नक–04)।**

5. सचिव, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, उ0प्र0 शासन लखनऊ के पत्र सं0–2810/9अ–1–98, दिनांक 23.09.1998 के द्वारा उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण उ0प्र0 एवं आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को निम्नवत् निर्देशित किया गया :–

1– प्राधिकरण/आवास विकास परिषद, नव विकसित कॉलोनियों के "ले–आउट प्लान" के अनुमोदन के पूर्व कॉलोनी के सीवेज, ड्रेनेज की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि सीवेज/ड्रेनेज उचित ट्रीटमेन्ट के पश्चात् ही नदियो में छोड़ा जाये। इस कार्य हेतु सर्विसेज का मास्टर प्लान जल निगम, प्राधिकरण के परामर्श व इनकी आर्थिक सहायता से बनायेंगे।

2– इसके अतिरिक्त गंगा नदी तट पर बसे नगरों से 200 मीटर तक किसी भी प्रकार की गतिविधियॉ अनुमन्य न की जाये **(संलग्नक–05)।**

6. सचिव, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, उ0प्र0 शासन लखनऊ के शासनादेश सं0 4503/9–आ–1–98, दिनांक 16.11.1998 के द्वारा जनहित चायिका संख्या 2155/97 राकेश कुमार जायसवाल बनाम राज्य सरकार विषयक में निम्नवत् निर्णय लिया गया **(संलग्नक–06):–**

1– गंगा नदी पर किनारे बसे नगरीय क्षेत्र में विकसित होने वाली कॉलोनियों के तलपट मानचित्रों के अनुमोदन से पूर्व यह सुनिश्चित होना आवश्यक है कि कॉलोनी के सीवर तथा ड्रेनेज से नदी प्रदूषित न हो तथा ट्रीटमेन्ट के पश्चात् ही से नदी में छोड़ा जाय।

2– ऐसे नगरों में नदी से 200 मीटर क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि अनुमन्य न की जाए।

3– उक्त निर्णय निजी निर्माताओं के साथ–साथ आवास विकास परिषद तथा प्राधिकरणों पर भी शासन रूप से लागू होगा। अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन के उक्त निर्णय का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

7. सचिव, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, उ0प्र0 शासन लखनऊ के शासनादेश सं0 320/9–आ–3–2000–127 काम्प/99, दिनांक 05.02.2000 में उल्लेख किया गया है कि शासनादेश दिनांक 23.09.1998 एवं 16.11.1998 के प्रस्तर–2 में गंगा नदी तट पर बसे नगरों में किनारे से 200 मी0 तक किसी भी प्रकार की गतिविधियॉ अनुमन्य न किये जाने का निर्गण लिया गया था। शासन द्वारा इस संबंध में सम्यक् विचारोंपरांत यह निर्गण लिया गया है कि उक्त प्रतिबन्ध को धार्मिक स्थलों, आश्रम एवं सार्वजनिक सुविधाओं के हित में किये जा रहे अन्य निर्माण कार्यों के लिए निम्नलिखित शर्तों के साथ शिथिल कर दिया जाय :–

1. हरित पट्टी के अनुरूप भूखण्ड के 10 प्रतिशत से अधिक भाग पर निर्माण अनुमन्य न होगा। एफ0ए0आर0 15 प्रतिशत से अधिक न होगा परन्तु यदि महायोजना में इससे कम अनुमन्य है तो उतना ही अनुमन्य होगा।
2. ड्रेनेज सीधे गंगा नदी में नहीं अवमुक्त किया जायेगा वरन् अन्य नालों आदि में ले जाने की व्यवस्था की जानी होगी।
3. यदि क्षेत्र में सीवेज व्यवस्था नहीं है तो निवास स्थान/धर्मशाला आदि इन प्रयोजनों में अनुमन्य नहीं की जायेगी ताकि गंगा नदी में मल न जाने पाये।

उपर्युक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 23.09.1998 एवं दिनांक 16.11.1998 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।''

सचिव आवास अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन लखनऊ के पत्र सं0 320/9–आ –3–2000–127 काम्प/99,दिनांक 05.02.2000 की छायाप्रति संलग्न है'' **(संलग्नक–07)**

8. मेसर्स पंचम रियलकॉन प्रा0लि0 के पत्र सं0 आर0इ0पी0एल0/इला0/हाई–टेकटा0/554, दिनांक 31.03.2011 के द्वारा प्रथम चरण कम्प्लीशन रिपोर्ट प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज को प्रेषित किया गया है **(संलग्नक–08)**

9. मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित जनहित याचिका (पी0आई0एल0) सं0 4003/2006 रि:गंगा पाल्यूशन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एण्ड अदर्स में मा0 न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 22.04.2011 को आदेश पारित किया गया है ''**(संलग्नक–09)**। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में गंगा नदी के किनारे निर्माण गतिविधियों के सम्बन्ध में निम्नवत् उल्लेख किया गया है:–

"....We thus direct that no construction shall be undertaken by the Allahabad Development authority or by any private builders within 500 meters of highest flood level of river Ganges in city of Allahabad as well as part of river Yamuna adjoining the river Ganges (Sangam). The Allahabad Development Authority and the district administration shall ensure that no construction be made in the aforesaid area. We however, give liberty to any aggrieved person to make appropriate application in this petition with regard to above restrictions, if he feels so aggrieved..."

10. मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित जनहित याचिका (पी0आई0एल0) सं0 4003/2006 रि: गंगा पाल्यूशन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 22.04.2011 के अनुपालन में प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज द्वारा अपने पत्र सं0 67/हा0टे0 से0/वि0प्रा0/2011, दिनांक 03.05.2011 के द्वारा मेसर्स पंचम रियलकॉन प्रा0लि0, प्रयागराज को स्थल पर कार्य रोकने के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया **(संलग्नक–10)**।

11. निरीक्षण के समय मेसर्स पंचम रियलकॉन प्रा0लि0 द्वारा ग्राम–देवरख उपरहार, देवरख कछार, चक विश्वनाथ, चकतेजुदिशी, मवई उपरहार, मढावन उपरहार एवं लवायनकलां तहसील–करछना, जनपद–प्रयागराज में निर्माण कार्य बन्द पाया गया। निरीक्षण के समय उक्त इकाई के निम्नवत् जिओ का–आर्डिनेट्स के मध्य निर्माण कार्य बन्द पाया गया :–

क्र0सं0	दिशा	जिओ को–आर्डिनेट्स	
		लैटीट्यूड	लांगीट्यूड
01	उत्तर दिशा	25.394404	81.894153
02	पश्चिम दिशा	25.39451	81.899282
03	दक्षिण दिशा	25.39301	81.90000
04	पूरब दिशा	25.39057	81.89507

इकाई द्वारा गंगा नदी के किनारे पूरब दिशा में निर्मित बाउण्ड्रीवॉल से पश्चिम दिशा में अरैल रोड के किनारे जिसकी दूरी लगभग 540 मीटर है, में निर्माण कार्य बन्द पाया गया।

निरीक्षण के समय उक्त संस्था के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित श्री तरूण शर्मा, डिप्टी जनरल मैंनेजर (लीगल) द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा जनहित याचिका (पी0आई0एल0) सं0 4003/2006 रि:गंगा पाल्यूशन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 22.04.2011 के क्रम में इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 03.05.2011 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया है।

12. मेसर्स पंचम रियलकॉन प्रा0लि0, प्रयागराज द्वारा दिनांक 01.02.2025 को लिखित रूप में सूचित किया गया है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 22.04.2011 को पारित आदेश के पूर्व परियोजना स्थल पर निम्नलिखित कार्य कराये गये थे:–

Project name	**Plot/Flat/Unit Constructed before Interim Stay dated 22.04.2011 by the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad**
Omaxe Sangam City Plot-Sector-1	550 Approx.
Omaxe Sangam City Villa (WF)-Sector-1	35 (under construction)
Water Front EWS-LIG Homes-Sector-1	90 (under construction)
Omaxe Duplex Villa Allahabad-Sector-1	13 (under construction)

उक्त के संबंध में इकाई द्वारा प्रस्तुत सूचना की हस्ताक्षरित प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है। **(संलग्नक–11)।**

13. निरीक्षण के समय मेसर्स पंचम रियलकॉन प्रा0लि0, प्रयागराज परिसर से लिये गये फोटोग्राफ्स संलग्न है **(संलग्नक–12)।**

14. निरीक्षण के समय मेसर्स पंचम रियलकॉन प्रा0लि0, प्रयागराज परिसर में अर्धनिर्मित एस0टी0पी0 स्ट्रक्चर पाया गया। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ संलग्न है **(संलग्नक–13)।**

15. मेसर्स पंचम रियलकॉन प्रा0लि0, प्रयागराज परिसर के पूरब–उत्तर दिशा में सटे लिंक रोड तत्पश्चात् गंगा नदी का किनारा स्थित है। निरीक्षण के समय मेसर्स पंचम रियलकॉन प्रा0लि0, प्रयागराज परिसर के बाउण्ड्रीवाल से गंगा नदी की मुख्य जलधारा लगभग 800 मी0 की दूरी पर प्रवाहित हो रही थी। गंगा नदी के फ्लड प्लेन जोन के डिमार्केशन के सम्बन्ध में सूचना इस कार्यालय के पत्र संख्या जी 01412/एन0जी0टी0 ओ0ए0 नं0 515/2023/2025, दिनांक 01.02.2025 के द्वारा अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, सिंचाई विभाग, प्रयागराज से मांगी गयी है **(संलग्नक–14)।** उक्त सूचना सिंचाई विभाग से अपेक्षित है।

उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

01/02/2025

(कौशल कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

01/2/25

संलग्नक -0

संख्या : 2608(1)/8–3–08–13विविध/08

प्रेषक,

श्री कृष्ण
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष
विकास प्राधिकरण,
लखनऊ, इलाहाबाद एवं बुलन्दशहर।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, लखनऊ दिनांक 03 जुलाई, 2009

विषय :– उ0प्र0 में निजी पूंजी निवेश के प्रोत्साहन हेतु हाईटेक टाउनशिप नीति–2007 के अन्तर्गत विकासकर्ता कम्पनी/कन्सोर्शियम का चयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि उ0प्र0 में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से हाईटेक टाउनशिप हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर डाक्यूमेन्ट फार सम्मिशन ऑफ एप्लीकेशन्स/प्रपोजल के मूल्यांकनोपरान्त विकासकर्ता कम्पनियों के चयन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 18.06.2009 को सम्पन्न हुयी उच्च स्तरीय समिति की बैठक में सम्यक विचारोपरान्त लखनऊ, इलाहाबाद एवं बुलन्दशहर में हाईटेक टाउनशिप नीति 2007 के अन्तर्गत निम्नलिखित विकासकर्ता कम्पनियों/कन्सोर्शियम का चयन किया गया :–

कमांक	विकासकर्ता कम्पनी/कन्सोर्शियम का नाम	प्रस्तावित टाउनशिप का जनपद	प्रस्तावित टाउनशिप हेतु क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	मेसर्स गर्ग प्रिल्डटेक प्रा0लि0	लखनऊ	2700.00
2	मेसर्स पंचम रियलकॉन प्रा0लि0	इलाहाबाद	1535.17
3	मेसर्स रिवाज इन्फ्राटेक प्रा0लि0	बुलन्दशहर	3601.19

2– उच्च स्तरीय समिति द्वारा उक्त हाईटेक टाउनशिप के क्षेत्रफल में भावी विस्तार के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्णय भी लिये गये है :–

1. क्षेत्रफल विस्तार की अधिकतम सीमा मूल क्षेत्रफल के बराबर होगी और यह विस्तार एक या दो बार में विकासकर्ता को इस शर्त के साथ दिया जायेगा कि प्रस्तावित विस्तार उनके नेटवर्थ के सापेक्ष अनुमन्य हो।

2. हाईटेक टाउनशिप के क्षेत्रफल में विस्तार की मांग मूल क्षेत्रफल के 50 प्रतिशत क्षेत्रफल में विकास करने के उपरान्त ही की जा सकेगी।

कृपया तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही तत्काल सम्पन्न कराने का कष्ट करे।

हस्ताक्षर

03.07.2009
(श्री कृष्ण)
प्रमुख सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. उच्च स्तरीय समिति के समस्त सदस्यगण।
2. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. महानिदेशक, कर एवं विपणन उ0प्र0।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 लखनऊ,
5. सम्बन्धित भूमि अध्याप्त अधिकारी।
6. अपर निदेशक, नियोजन आवास बन्धु, उ0प्र0 लखन को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. सम्बन्धित विकासकर्ता।

आज्ञा से

03.07.2009
(राम निरंजन)
अनु सचिव

संलग्नक-(2)

Annexure - 2

51

ANNEXURE-A/2

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद।

प्रेषक,

नगर नियोजक,
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।

सेवा में,

मेसर्स पंचम रियलकॉन प्रा०लि०
नियासी-10, लोकल शापिंग सेन्टर (एल०एस०सी०)
पोस्ट आफिस कालकाजी,
नई दिल्ली-110019

पत्रांक 598/हाईटेक टाउनशिप/नगर नियोजक/वि०प्रा०/2009 दिनांक 24/10/09

विषयःजनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत ग्राम देवरख उपरहार, देवरख कछार, चक विश्वनाथ मकतेज्ज दीक्षित, मवैया उपरहार, मदनुवा उपरहार, तथा लवायन कलां, गडुना अरैल तहसील-करछना, में हाईटेक टाउनशिप के विकास हेतु मेसर्स पंचम रियलकॉन प्रा०लि० द्वारा प्रस्तुत संशोधित कन्सेप्चुयल डी०पी०आर के अनुमोदन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा गठित डी०पी०आर० समिति की बैठक दिनांक 11.09.2009 में समिति द्वारा उठाये गये बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में आप द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रस्तरवार आख्या का परीक्षण स्थानीय स्तर पर कराते हुए कमियां/सुझावों का एक तुलनात्मक विवरण के साथ हाईटेक टाउनशिप के विकास हेतु आप द्वारा प्रस्तुत संशोधित कन्सेप्चुयल डी०पी०आर के अनुमोदन के संबंध में प्रस्ताव विकास प्राधिकरण बैठक दिनांक 08.10.2009 के मद संख्या-8 के अन्तर्गत विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत किया गया था, जिसमें प्राधिकरण बैठक के संकल्प संख्या-1516 के अन्तर्गत यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत डी०पी०आर० की स्वीकृति सर्वसम्मति से सशर्त की गयी, जिसके अनुसार समिति द्वारा दिये गये सुझावों के अनुक्रम में अवशेष शर्तो को निर्माण/विकास एग्रीमेंट के समय मेसर्स पंचम रियलकॉन प्रा०लि० द्वारा आवश्यक रूप से पूर्ण किया जाये। जो शर्तो निर्धारित की गयी है वह बिन्दु क्र संख्या 1.3, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 6.5, 6.8, 6.9, 6.11, 6.12, 7.3, 7.5, 10.3 तथा 11.0 में कार्यवाही अपेक्षित है।

अतः उपर्युक्त शर्तो के अधीन आप द्वारा संशोधित कन्सेप्चुअल डी०पी०आर० की अनुमोदित प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकःयथोपरि।

भवदीय
24.10.09
(स्वराज गांगुली)
नगर नियोजक

संलग्नक - (3)

55

Annexure-3

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh
Directorate of Environment, U.P.

Ref. No. 226/SEAC/358/2009/TA(J)/ Date: 10 February, 2010
M/s Pancham Realcon Pvt. Ltd.
10 LSC Kalkaji, New Delhi.

Sub : Regarding the Environmental Clearance for Proposed "Hi-tech-Township" at village-Devrakh Upperhar, Devrakh Kacchahar, Chak-Vishonath, Chak-Teju Dishi, Mavai-Upperhar, Madhanwan Upperhar and Lavayan Kalan, District-Allahabad, U.P. of M/s, Pancham Realcon Pvt. Ltd.

Dear Sir,

Please refer to your letter dated 03.10.2009 addressed to the Secretary, State Level Expert Appraisal Committee, Directorate of Environment, U.P. Paryavaran Parisar, Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow on the subject as above. The State Level Expert Appraisal Committee has considered your application and has been given to understand that:

1. The Environmental Clearance is sought for proposed "Hi-tech Township" at village- Devrakh Upperhar, Devrakh Kacchahar, Chak-Vishonath, Chak-Teju Dishi, Mavai-Upperhar, Madhanwan Upperhar and Lavayan Kalan, District-Allahabad, U.P. of M/s Pancham Realcom Pvt. Ltd.

2. The total plot area is 1535.12 Acres and total built up area is 8537950.52 sq.mt.

Area Distribution as following:

- Plotted : 1039840.00 sq.mt.
- Group Housing : 1373632.39 sq.mt.
- Commercial : 413158.23 sq.mt.
- Public/Semi Public : 540517.32 sq.mt.
- Industrial : 505713.12 sq.mt.
- Recreational : 220966.2 sq.mt.

3. The project is covered under screen category: 8 "b"

The Committee was given to understand that the clearance is being sought only for infrastructural development. Individual activities under the categories of development as above would take separate environmental clearance as applicable. The committee was also informed that the responsibility of the developers is to acquire the land, develop the road network lay outing of the residential, commercial, industrial and green areas, making arrangements for supply of power, water and communication system and making provisions for management of drainage waste water and solid waste. Accordingly no major construction activities in terms of civil structures are envisaged.

Based on the recommendations of the State Level Exert Appraisal Committee (Meeting held on 22/12/2009 on the aforesaid project the State Level Environment Impact Assessment Authority (Meeting held on 22-01-2010) has decided to grant the Environmental Clearance to the Project subject to the effective implementation of the following conditions:

a. <u>General Conditions:</u>

1. It shall be ensured that all standards related to ambient environment quality and the emission/effluent standards as prescribed by the MoEF are strictly complied with.
2. It shall be ensured that obtain the no objection certificate from the U.P. pollution control board before start of construction.
3. It shall be ensured that no construction work or preparation of land by the project management except for secured securing the land is started on the project or the activity without the prior environmental clearance.

4. The proposed land use shall be in accordance to the prescribed land use. A land use certificate issued by the competent authority shall be obtained in this regards.
5. All trees felling in the project area shall all be as permitted by the forest department under the prescribed rules. Suitable clearance in this regard shall be obtained from the competent authority.
6. Impact of drainage pattern on environment should be provided.
7. Surface hydrology and water regime of the project area within 10 km. should be provided.
8. A suitable plan for providing shelter, light and fuel, water and waste disposal for construction labour during the construction phase shall be provided along with the number of proposed workers.
9. Measures shall be undertaken to recycle and reuse treated effluents for horticulture and plantation. A suitable plan for waste water recycling shall be submitted.
10. Cbtain proper permission from competent authorities regarding enhanced traffic during and due to construction and operation of project.
11. Obtain necessary clearances from the competent authority on the abstraction and use of ground water during the construction and operation phases.
12. Hazardous/Inflammable/Explosive material likely to be stored during the construction and operation phases shall be as per standard procedure as prescribed under law. Necessary clearances in this regards shall be obtained.
13. Solid wastes shall be suitably segregated and disposed. A separate and isolated municipal waste collection center should be provided. Necessary plans should be submitted in this regards.
14. Suitable rainwater harvesting systems as per, designs of groundwater department shall be installed. Complete proposals in this regard should be submitted.
15. The emissions and effluents etc. from machines, instruments and transport during construction and operation phases should be according to the prescribed standards. Necessary plans in this regard shall be submitted.
16. Water sprinklers and other dust control measures should be undertaken to take care of dust generated during the construction and operation phases, Necessary plans in this regard shall be submitted.
17. Suitable noise abatement measures shall be adopted during the construction and operation phases in order to ensure that the noise emissions do not violate the prescribed ambient noise standards. Necessary plans in this regard shall be submitted.
18. Separate stock piles shall be maintained for excavated top soil and top soil should be utilized for preparation of green belt.
19. Sewage effluents shall be kept separate from rain water collection and storage system and separately disposed. Other effluents should not be allowed to mix with domestic effluents.
20. Hazardous/Solid wastes generated during construction and operation phases should be disposed off as prescribed under law. Necessary clearances in this regard shall be obtained.
21. Alternate technologies for solid waste disposals (like vermin-culture etc.) should be used in consultation with expert organizations.
22. No wetland should be infringed during construction and operation phases. Any wetland coming in the project area should be suitably rejuvenated and conserved.
23. Pavements shall be so constructed as to allow infiltration of surface run-off of rain water. Fully impermeable pavements shall not be constructed. Construction of pavements around trees shall be as per scientifically accepted principles in order to provide suitable watering, aeration and nutrition of the tree.
24. The Green building Concept suggested by Indian Green Building Council, which is a part of CII- Godrej GBC, shall be studied and followed as for as possible.
25. Compliance with the safety procedures, norms and guideilnes as outlined in National Building Code 2005 shall be compulsorily ensured.
26. Ensure usage of dual flush systems for flush cisterns and explore options to use sensor based fixture, waterless urinals and other water saving techniques.

5755

27. Explore options for use of dual pips plumbing for use of water with different qualities such as municipal supply, recycled water ground water etc.
28. Ensure use of measures for reducing water demand for landscaping and using xeriscaping, efficient irrigation equipments & controlled watering systems.
29. Make suitable provisions for using solar energy as alternative source of energy. Solar energy application should be incorporated for illumination of common areas, lighting for garden and street lighting in addition to provision for solar water heating. Present a detailed report showing how much percentage of backup power for institution can be provided through solar energy so that use and polluting effects of DG sets can be minimized.
30. Make separate provision for segregation, collection, transport and disposal of e-waste.
31. Educate citizens and other stake-holders by putting up hoardings at different places to create environmental awareness.
32. Traffic congestion near the entry and exist points from the roads adjoining the proposed project site must be avoided. Parking should be fully internalized and no public space should be utilized.
33. Prepare and present disaster management plan.
34. The project proponents shall ensures that no construction activity is undertaken without obtaining pre-environmental clearance.
35. A report on the energy conservation measures confirming to energy conservation norms finalize by Bureau of Energy efficiency should be prepared incorporating details about building materials and technology, R& U. Factors etc.
36. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provision of fly ash notification of September, 1999 and amended as on August, 2003 (The above condition is applicable only if the project lies within 100 km. of Thermal Power Station).
37. The DG sets to be used during construction phase should use low sulphur diesel type and should conform to E.P. rules prescribed for air and noise emission standards.
38. Alternate technologies to Chlorination (for disinfection of waste water) including methods like Ultra Violet radiation, Ozonation etc. shall be examined and a report submitted with justification for selected technology.
39. The green belt design along the periphery of the plot shall achieve attenuation factor conforming to the day and night noise standards prescribed for residential land use. The open spaces inside the plot should be suitably landscaped and covered with vegetation of indigenous variety.
40. The construction of the building and the consequent increased traffic load should be such that the micro climate of the area is not adversely affected.
41. The building should be designed so as to take sufficient safeguards regarding seismic zone sensitivity.
42. High rise buildings should obtain clearance from aviation department or concerned authority as applicable.
43. Suitable measures shall be taken to restrain the development of small commercial activities or slums in the vicinity of the complex. All commercial activities should be restricted to special areas earmarked for the purpose.
44. It is suggested that literacy program for weaker sections of society/women/adults (including domestic help) and under privileged children could be provided in a formal way.
45. That use of Compact Fluorescent lamps should be encouraged. A management plan for the state disposal of used/damaged CFLs should be submitted.
46. It shall be ensured that all Street and park lighting is solar powered. 50% of the same may be provided with dual (solar/electrical) alternative.
47. Solar water heater shall be installed to the maximum possible capacity. Plans may be drown up accordingly ad submitted with justification.
48. Treated effluents shall be maximally roused to aim for zero discharge. Wherever not possible. A detailed management plan for disposal should be provided with quantities and quality of waste water.

49. The treated effluents should normally not be discharged into public sewers with terminal treatment facilities as they adversely affect the hydraulic capacity of STP. If unable, necessary permission form authorities should be taken.
50. Construction activities including movements of vehicles should be so managed so that no disturbance is caused to nearby residents.
51. All necessary statuary clearances should be obtained and submitted before start of any construction activity and if this condition is violated the clearance, if and when given, shall be automatically deemed to have been cancelled.
52. Parking areas should be in accordance with the norms of MOEF, Government of India, Plans may be drawn up accordingly and submitted.
53. The local of the STP should be such that it is away from human habilitation and does not cause problem of odor. Odorless technology options should be examined and a report submitted.
54. The Environment Management plan should also include the break up costs on various activities and the management issues also so that the residents also participate in the implementation of the environment management plan.
55. Detailed plans for safe disposal of STP sludge shall be provided along with ultimate disposal location, quantitative estimates and measures proposed.
56. Status of the project as on ... shall be submitted along with photographs from North, South, West and East side facing camera and adjoining areas should be provided.
57. Specific location along with dimensions with reference to STP, Parking, Open areas and Green belt etc. should be provided on the layout plan.
58. The DG sets shall be so installed so as to conform to prescribed stock heights and regulations and also to the noise standards as prescribed, Details should be submitted.
59. E-Waste Management should be done as per MoEF guidelines.
60. Electrical waste should be segregated and disposed suitably as not to impose Environmental Risk.
61. The use of suitably processed plastic waste in the construction of roads should be considered.
62. Displaced persons shall be suitably rehabilitated as per prescribed norms.
63. Dispensary for first aid shall be provided.
64. Health impacts, Socio-economic impacts, soil degradation factors and bio-diversity indices should also be include in E.I.A. reports.
65. Safe disposal arrangement of used toiletries items in hotels should be ensured. Toiletries items could be given complementary to guests, adopting suitable measures.
66. Diesel generating set stacks should be monitored for CO and HC.
67. Ground Water downstream of Rain water Harvesting pit nearest to STP should be monitored for bacterial contamination, Necessary Hand Pumps should be provided for sampling. The monitoring is to be done both in pre and post monsoon, seasons.
68. The green belt shall consist of 50% trees, 25% grass as per MoEF norms.
69. A separate electric mater shall be provided to monitor consumption of energy for the operation of sewage/effluent treatment in tanks.
70. An energy audit should be annually carried out during the operational phase and submitted to the authority.

b. **Specific Conditions:**

1. Only non-polluting industries should be allowed.
2. The possibility to use surface water instead of ground water should explore.
3. Water requirement should be based on norms prescribed in MoEF construction manual.
4. A separate escrow account shall be opened for execution and maintenance of Environment Management Plan. The details of activity regarding, environment [illegible]

5. A suitable plan for providing shelter, light and fuel and for disposal of water and waste during the construction phase shall be provided for proposed workers as per direction of MoEF.
6. Water uses for horticulture shall be restricted to 1 lt /sq. mt.
7. A comprehensive ELA shall be undertaken before commencement of the construction and the Environment Management Plan (EMP) and Detailed Project Report (DPR) revised accordingly taking into view conditions stipulated in this clearance. The report shall be submitted to this Authority by January, 2011, felling which the clearance will automatically deemed to be cancelled.

The project proponent will have to submit approved plans and proposals incorporating the conditions specified in the Environmental Clearance within 03 month of issue of the clearance. Falling this the environmental Clearance shall be deemed to be cancelled.

Necessary statutory clearances should be obtained and submitted before start of any construction activity in the event of the violation of the condition the environmental clearance shall be automatically deemed to have cancelled.

These stipulations would be enforced among others under the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, the Public liability (Insurance) Act 1991 and EIA Notification 2006 including the amendments and rules made thereafter.

This is to request you to take further necessary action in matter as per provision of Gazette Notification No. S.O. 1533(E) date 14.09.2006 and send regular compliance report to the authority as prescribed in the aforesaid notification.

(Dr. C.I. Bhatt)
Member Secretary, SEIAA

<u>Copy for necessary action to</u>:

1. The Principal Secretary Environment U.P. Government Lucknow.
2. Dr. Nalini Bhatt, Director Ministry of Environment & Forest Government of India Paryavaran Bhavan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi.
3. Regional Office, Ministry of Environment & Forest, (Center Forest), Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow.
4. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, PICUP Bhawan, Gomti Nagar, Lucknow.
5. Administration officer, Directorate of Environment for Monitoring & Web Updation.

(Dr. Yashpal Singh)
Secretary, SEAC and
Director, Environment Directorate,
Govt. of U.P.

संलग्नक - (4)

136

ANNEXURE-A/3

संदर्भ संख्या F66176 सी–3/एन0 ओ0 सी0/3556/2010

दिनांक 05.05.10

सेवा में,

मे0 पंचम रियलकॉन प्रा0 लि0 (ओमेक्स लि0)

देवघाट, नैनी, इलाहाबाद

विषय – पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से/नई इकाई की स्थापना हेतु/ कार्यरत इकाई की उत्पादन क्षमता में विस्तार संयंत्रों के नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र ——— जल (प्रदूषण निवारण एवं तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25/26 व वायु (प्रदूषण निवारण एवं तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21/22।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक शून्य का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों संलग्न के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिये निर्गत किया जा रहा है।

(क) स्थल ग्रा देवघाट उपरहार, देवघाट कछार, चक विश्वनाथ, चक तेजवा दीक्षित, मवैया उपरहार, मेदनुआ उपरहार, लवायन कला उपरहार इलाहाबाद

(ख) प्लाटस । वर्ग मीटर

ग्रुप हाउसिंग । 1039847.00 वर्ग मीटर

कामर्शियल : 137363275 वर्ग मीटर

पब्लिक/सेमी पब्लिक : 413158.26 वर्ग मीटर

इन्डस्ट्रियल : 540537.32 वर्ग मीटर

रिक्रियेशन्स । 220980.20 वर्ग मीटर

(ग) मुख्य कच्चे माल : बिल्डिंग मैटेरियल

(घ) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा : शून्य

ऊर्जा आवश्यकतानुसार

उपर्युक्त निम्न वस्तु में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने से पूर्व अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापनाओं में हो रही प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।

3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अंतर्गत सहमति प्राप्त न कर ले। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुये इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाय। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

4. उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाए।

5. घरेलू उत्प्रवाह जिसकी मात्रा 31.08 के0 एल0 डी0 से अधिक नहीं होगी। सेप्टिक टैंक एवं सोक पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाये।

6. प्रदूषण नियन्त्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण, क्रय, आपूर्ति के लिये दिये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक 30.08.2010 तक अवश्य प्रस्तुत की जाये।

7. प्रस्तावित टाउनशिप परियोजना हेतु स्टेट लेवल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एसेसमेन्ट अथारिटी, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 12 फरवरी 2010 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।

8. परियोजना से जनित घरेलू जल मल के शुद्धिकरण हेतु प्रस्तावित सीवेज उपचार संयंत्र की स्थापना के उपरान्त ही आवासीय योजना का संचालन सुनिश्चित किया जाये तथा शुद्धिकृत उत्प्रवाह का उपयोग परिसर में गार्डेनिंग एवं ग्रीन बेल्ट विकसित करने हेतु किया जाये।

9. परियोजना से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट का निस्तारण नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं प्रचालन) नियम, 2000 के प्राविधानों के अनुसार किया जाये।

10. परियोजना का संचालन राज्य बोर्ड से जल/वायु सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही सुनिश्चित किया जायेगा।

11. परियोजना में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था स्थापित करना सुनिश्चित करें।

138

... साइट स्थापित किया जाए तथा

उक्त हेतु प्रस्ताव एक माह में जमा किया जाये।

18. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन हेतु 10.0 लाख की बैंक गारन्टी 15 दिन में बोर्ड में जमा कराना सुनिश्चित करें। शर्तों का अनुपालन न होने पर जमा की गयी बैंक गारन्टी बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त की जा सकती है। निर्धारित अवधि में बैंक गारन्टी प्राप्त न होने पर बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकता है।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण – पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाये। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 30.06.2010 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाये। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय,

(डा0 सी0 एस0 भट्ट)

सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं० ____ /एन. ओ. सी तद दिनांक

प्रतिलिपिः

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, इलाहाबाद
2. उपकर अधिकारी, उ0 प्र0 नियंत्रण, लखनऊ
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इलाहाबाद

मुख्य पर्यावरण

(सकिंल / 2)

(सत्य प्रतिलिपि)

संलग्नक-5

214

~~1144~~ ~~2117~~
(9)

संख्या: 2810/9-आ-1-98

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

2. आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

आवास अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 23 सितम्बर, 1998

विषय:- माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन याचिका संख्या: 21552/97 के संदर्भ में नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए नव विकसित कालोनियों में सीवेज, ड्रेनेज की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राधिकरण/आवास विकास परिषद, नवविकसित कालोनियों के "ले-आउट प्लान" के अनुमोदन के पूर्व कालोनी के सीवेज, ड्रेनेज की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि सीवेज/ड्रेनेज उचित ट्रीटमेन्ट के पश्चात ही नदियों में छोड़ा जाय। इस कार्य हेतु "सीवरेज" का "मास्टर प्लान" जल निगम/प्राधिकरण के परामर्श व इनकी आर्थिक सहायता से बनायेंगे।

2. इसके अतिरिक्त गंगा नदी तट पर बसे नगरों में किनारे से 200 मीटर तक किसी भी प्रकार की गतिविधियाँ अनुमन्य न की जायें।

भवदीय,
(अतुल कुमार गुप्ता)
सचिव

संख्या: 2810/ /9आ-1-98, तद्दिनांक।

1. प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता (गंगा) एवं नोडल अधिकारी, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि सचिव, नगर विकास को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जल निगम को तदनुसार कार्यवाही प्राथमिकता पर करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

([illegible]किशोर सिंह)
अनुसचिव।

संलग्नक-(6)

1462

(11)

संख्या–4503/9–आ–1–1998

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
   उ.प्र. आवास एवं विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,
   समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक
   नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र. लखनऊ।

आवास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 16 नवम्बर, 1998

विषय : जनहित याचिका संख्या 2155/97 राकेश कुमार जैसवाल बनाम राज्य सरकार।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि :–

1. गंगा नदी पर किनारे बसे नगरीय क्षेत्र में विकसित होने वाली कालोनियों के तलपट मानचित्रों के अनुमोदन से पूर्व यह सुनिश्चित होना आवश्यक है कि कालोनी के सीवर तथा ड्रेनेज से नदी प्रदूषित न हो तथा ट्रीटमेन्ट के पश्चात ही से नदी में छोड़ा जाय।
2. ऐसे नगरों में नदी से 200 मीटर क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि अनुमन्य न की जाए।
3. उक्त निर्णय निजी निर्माताओं के साथ–साथ आवास विकास परिषद तथा प्राधिकरणों पर भी शासन रूप से लागू होगा। अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन के उक्त निर्णय का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संलग्नक - (7)

(IZ)

संख्या–320/9–आ–3–2000–127 काम्प/99

प्रेषक,
अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
   समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. आवास आयुक्त,
   उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
   नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश,
   लखनऊ।

आवास अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 05 फरवरी, 2000

विषय : गंगा नंदी तट पर बसे नगरों में किनारे से 200 मीटर तक किसी भी प्रकार की गतिविधियाँ अनुमन्य न किये जाने के प्रतिबन्ध को शिथिल किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–2810/9–आ–1–98, दिनांक 23 सितम्बर, 1998 एवं शासनादेश संख्या–4503/9–आ–1–98, दिनांक 16 नवम्बर, 1998 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेशों के प्रस्तर–2 में गंगा नदी तट पर बसे नगरों में किनारे से 200 मीटर तक किसी भी प्रकार की गतिविधियाँ अनुमन्य न किये जाने का निर्णय लिया गया था। शासन द्वारा इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उक्त प्रतिबन्ध को धार्मिक स्थलों, आश्रम एवं सार्वजनिक सुविधाओं के हित में किये जा रहे अन्य निर्माण कार्यों के लिये निम्नलिखित शर्तो के साथ शिथिल कर दिया जाय :–

1. हरित पट्टी के अनुरूप भूखण्ड के 10 प्रतिशत से अधिक भाग पर निर्माण अनुमन्य न होगा। एफ0ए0आर0 15 प्रतिशत से अधिक न होगा परन्तु यदि महायोजना में इससे कम अनुमन्य है तो उतना ही अनुमन्य होगा।

278

148 ~~251~~

(~~13~~)

2. ड्रेनेज सीधे गंगा नदी में नहीं अवमुक्त किया जायेगा वरन् अन्य नालों आदि में ले जाने की व्यवस्था की जानी होगी।
3. यदि क्षेत्र में सीवेज व्यवस्था नहीं है तो निवास स्थान/धर्मशाला आदि इन प्रयोजनों में अनुमन्य नहीं की जायेगी ताकि गंगा नदी में मल न जाने पाये।

उपर्युक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 23–9–98 एवं दिनांक 16–11–98 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या–320/9–आ–3–2000–127 काम्प/99 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1. मुख्य अभियन्ता (गंगा) एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
2. सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास विभाग।
3. उपाध्यक्ष, समस्त विषेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से
जावेद एहतशाम
उप सचिव।

संलग्नक - (8)

197

(3.)

OMAXE
making dreams into reality

WATER FRONT
OMAXE HI-Tech City, Allahabad

पत्रांक संख्या : आर0ई0पी0एल0 / इला0 / हाई-टेक टा0 / 554

दिनांक : 31.03.2011

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।

विषय–इलाहाबाद हाईटेक टाउनशिप के प्रथम चरण के कम्पलीशन सर्टिफिकेट निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपसे अनुरोध करना है कि मेसर्स पंचम रियलकॉन प्रा0लि0 द्वारा हाईटेक टाउनशिप इलाहाबाद के सेक्टर-1 के सभी विकास कार्य पूर्ण कर लिये गये है जो निर्धारित पत्र पर सूचनायें भरकर आपके समक्ष मानचित्रों के साथ प्रेषित की जा रही है। कृपया कम्पलीशन सर्टिफिकेट जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नक :

1. ले-आउट मानचित्र (तीन प्रति) +1
2. इक्स्टरनल ड्रेनेज नेटवर्क मानचित्र (तीन प्रति) +1
3. इन्टरनल ड्रेनेज नेटवर्क मानचित्र (तीन प्रति) +1
4. ओ0एच0टी0, टी0डब्लू0, यू0जी0टी0 मानचित्र (तीन प्रति) +1
5. 9मी0 वाइड रोड सेक्शन मानचित्र (तीन प्रति) +1
6. 12मी0 वाइड रोड सेक्शन मानचित्र (तीन प्रति) +1
7. 18मी0 वाइड रोड सेक्शन मानचित्र (ए टू बी सी टू डी) (तीन प्रति) +1
8. रेन वाटर हार्वेस्टिंग डिटेल मानचित्र (तीन प्रति) +1
9. सीवरेज नेटवर्क मानचित्र (तीन प्रति) +1
10. लैण्ड स्केपिंग मानचित्र (तीन प्रति) +1
11. स्ट्रीट लाइटिंग मानचित्र (तीन प्रति) +1
12. वॉटर सप्लाई मानचित्र (तीन प्रति)

भवदीय

(अजय मिश्र)
अधि0 हस्ताक्षरी
मेसर्स पंचम रियलकॉन प्रा0 लि0

PANCHAM REALCON PVT. LTD.
(A SPV of OMAXE LTD.)
Regional Office: N/A/2, 2nd Floor, Civil Station, Tashkent Marg, Allahabad - 211001
Tel No.: 0532-6597882, 6597883, Fax: 0532-2260453
Regd. Office: 10, L.S.C., Kalkaji, New Delhi Tel.: 011-41896776 / 6680 / 6634 / 3100
E-mail : info@omaxefront.com website : www.omaxe.com

संलग्नक-(9)

ANNEXURE-A/6

Court No. - 2

Case :- PUBLIC INTEREST LITIGATION (PIL) No. - 4003 of 2006
Petitioner :- Re: Ganga Pollution
Respondent :- State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- Vijay Chandra Srivastava,A.K. Gupta,A.K. Srivastava,Anil Tiwari,Arun Kumar,Arvind Agarwal,Baij Nath Yadav,Baleshwar Chaturvedi,D.B. Mishra,D.S. Mishra,Jagdish Tewari,K.C. Pandey,P.N. Mishra,S.K. Srivastava,Shailesh Singh,Sharad Kr. Srivastava,Sunita Sharma,V.B. Singh,V.C. Mishra,Vivek Mishra
Respondent Counsel :- C.S.C.,A.K. Mishra,Ajay Bhanot,Anjani Kumar Mishra,C.L.Pandey,Chandan Sharma,Dr. H.N.Tripathi,H.N. Singh,Hem Pratap Singh,Iqbal Ahmad,M.C. Chaturvedi,N. Misra,P.S. Baghel,R.B. Shukla,Rajiv Lochan Shukla,S.A. Lari,S.M.A. Kazmi,S.P. Kesharwani,S.P. Singh,T.M.Khan,Vivek Birla,Vivek Verma,W.A. Hashmi

---

Hon'ble Ashok Bhushan,J.

Hon'ble Arun Tandon,J.

Heard Dr. Ashok Nigam, learned Additional Solicitor General of India, assisted by Sri Ajay Bhanot for Union of India, Sri U.N. Sharma, learned Senior Advocate, special counsel for the State of U.P., Sri S.G. Husnain, learned Additional Advocate General assisted by Sri S.P. Kesharwani, learned Additional Chief Standing Counsel for the State, Dr. H.N. Tripathi, learned counsel for U.P. Pollution Control Board, Sri S.D. Kautilya, learned counsel for Municipal Corporation, Allahabad, Sri Rajeev Lochan Shukla, learned counsel for the Tanneries and Sri A.K. Gupta, learned amicus curiae as well as Sri Ashwani Kumar Misra, learned counsel appearing for newly impleaded respondent, Allahabad Development Authority.

Learned amicus curiae has filed an application for impleadment of the State Level Environment Impact Assessment authority, Uttar Pradesh, through its Member Secretary, Pickup Bhawan, Gomti, Nagar, Lucknow and Allahabad Development Authority though its Vice Chairman, Indira Bhawan, Civil Lines, Allahabad as respondents No. 18 and 19. The impleadment application is allowed.

An application for impleadment has also been filed on behalf of Allahabad Development Authority through Sri Ashwani Kumar Misra Advocate along with application for vacating the order dated 28.3.2011 supported by a detailed affidavit. The application and affidavit are taken on record. The impleadment of Allahabad Development Authority has already been allowed.

Learned Additional Solicitor General with regard to transfer of a Defence land area 1123.80 square meters at Mori Gate Fort, Cantt. Allahabad for the purpose of establishing the sewage pumping station, has submitted that the letter dated 28.1.2011 has been issued by the Government of India, Ministry of Defence informing the Principal Secretary, Government of U.P. that in principle approval for permitting State Government of Uttar Pradesh/Ganga Pollution Control Unit for construction of a sewage pumping station on the aforesaid land has been granted. The consent of the State Government as per current Standard Table of Rents (STR) and not as per the circle rate of the State Government has been sought. No appropriate reply has been given by the learned counsel appearing for the State as to why the aforesaid concurrence has not been yet been communicated to the Ministry of Defence, whereas establishing a sewage pumping station at Mori Gate is urgently required. However, in the affidavit dated 28.3.2011 sworn by Sri Anil Kumar Srivastava, Managing Director, U.P. Jal Nigam, Lucknow, a copy of the Government order dated 19.2.2011 has been filed as Annexure-6 by which order, the State Government has communicated the Commissioner, Allahabad Division and District Magistrate, Allahabad and Nagar Ayukt, Nagar Nigam, Allahabad to take appropriate action as per the letter of the Central Government dated 28.1.2011. The said letter clearly thus conveys the State Government's concurrence to the letter dated 28.1.2011

and the authorities aforesaid were directed to take appropriate action. Another letter dated 25.2.2011 written by Lt. Col. A.S. Dabholkar has been annexed by which the General Manager Ganga Pollution Control Unit was requested to work out the cost of the Defence Land as per current (effective) Standard Table of Rent (STR) and forward the same to DG, DE New Delhi. From the aforesaid correspondences, which have been brought on record along with the aforesaid affidavit, it is clear that although the Central Government has communicated its concurrence for transfer of the Defence land as per current (effective) Standard Table of Rent but due to not taking effective compliance by the authority concerned, the working permission for construction of sewage pumping station could not be issued by Ministry of Defence.

Sri S.G. Hasnain, learned Additional Advocate General sought to contend that the State Government has given its permission to transfer the land on circle rate which arguments has no leg to stand when the Ministry of Defence has already communicated their concurrence for transfer of the land on current Standard Table of Rent (STR) and the land belong to the Ministry of Defence, it is not open for the Additional Advocate General to contend that the cost of the land is to be made by circle rate. The above argument itself suggests that the State Government is not effectively taking consequential steps, which is failing the transfer of Defence land.

We direct the State authorities including the District Magistrate, Allahabad to immediately communicate their approval for the transfer of land on the valuation as per Standard Table of Rents. All effective steps in this context be taken within two weeks and the Ministry of Defence shall accordingly issue working permission for construction of sewage pumping station within four weeks thereafter so that the construction of sewage pumping station be started.

Sri Ajay Bhanot, learned counsel appearing for the Union of India has also submitted that the issue of minimum flow of water in river is being considered by a sub committee constituted on October 4, 2010 the report of which is awaited. He has referred to affidavit of Sri Sudhir Garg, filed on behalf of Ministry of Water Resources, Government of India, New Delhi dated 27.3.2011. From the aforesaid counter affidavit, it is clear that Water Quality Assessment Authority, New Delhi was constituted by the Government of India in the year 2001. A decision was taken on 14.5.2003 by the said Authority to constitute a working group with the terms of reference which also included studies towards deciding minimum flows in the river and other related issues. The report is said to be submitted in July, 2007, recommending that legal and institutional implications of the report may be examined by a committee under the Chairmanship of Chief Engineer, CWC. A report in this regard has been submitted on October 27, 2009 which was discussed on 11.10.2010 by Water Quality Assessment Authority when it was agreed that a sub committee be constituted. As noticed in earlier orders of this Court two of the issues which need to be considered are as as follows:

(a) Can the State draw unlimited quantity of water from a river even to the extent of rendering its main stream a dry zone?

(b) Can the State because of drawl of water from upper portion of the river Ganges render its quantity or quality of water completely unfit for human use even for abthing purposes?

The aforesaid facts indicate that the issue of minimum flow of

water in a river is engaging attention of various authorities and Committees of Ministry of Government of India for long about a decade but no final recommendation in this regard could be made. Sri Ajay Bhanot appearing for the Union has submitted that a report in this regard shall be shortly submitted and brought before the Court. We notice that large number of issues are being considered by Water Quality Assessment Authority but for the purpose of this case, recommendation/ report is required on following two issues:

(i) Standards regarding quality of water in river Ganges which is fit for drinking and bathing purposes.

(ii) issues '(a)' and '(b)' as quoted above with regard to minimum flow of water in river Ganges.

In view of the aforesaid, we direct the Ministry of Water Resources as well as Ministry of Environment and Forest to take immediate steps in this regard so as the appropriate recommendation/report in that regard be submitted and brought before the Court within a period of three weeks from today.

Along with counter affidavit of Sri S.K. Sarcar filed on behalf of Ministry of Urban Development Government of India, New Delhi dated 25.1.2011, the Government of India has brought on record the inspection report of the expert committee which was constituted in pursuance of the order of this Court dated 6.12.2010 passed in this petition. The Committee was directed to inspect the laying down of the sewer line and if necessary by digging the sewer line to find out whether the sewer line work done, was in accordance with the approved DPR. U.P. Jal Nigam was also directed to take necessary steps in that regard. The expert committee constituted by the Ministry of Urban Development Government of India visited the

city of Allahabad on 29th and 30th December, 2010 and inspected the works and submitted its report which has been filed as Annexure-C.A- 1. The report brought on record indicates that there has been variation in actual work undertaken regarding laying down of the sewer line in accordance with the approved DPR. Several shortcomings and violations of D.P.R. have been pointed out in the inspection report.

An affidavit on behalf of U.P. Jal Nigam has been filed in this regard. The affidavit filed by U.P. Jal Nigam is sketchy and does not refer to any action taken by the U.P. Jal Nigam, which is the implementing agency for laying down sewer line in reference to the inspection report of the expert committee. Sri Ravi Kant, learned Senior Advocate appearing for U.P,. Jal Nigam has prayed for time to take effective steps and file a proper affidavit in this regard. As prayed three weeks' time is allowed. The appropriate direction in this context shall be issued after filing of the affidavit by U.P. Jal Nigam.

This Court vide order dated 19.1.2011 had issued following directions:

> *"It was pointed out by learned Amicus Curiae that the colour and quality of the water at Sangam and several other places has deteriorated and the colour has become red and brown which clearly suggests that the quality of the water has deteriorated due to unabated pollution of river water including the pollution at Kanpur Nagar and other cities.*
>
> *Dr. H.N. Tripathi, who is present for the U.P.*

Pollution Control Board, has filed affidavit bringing the report regarding analysis of the water which confirms that water quality has deteriorated. We fail to understand that the river water is continuously being polluted and the quality is going bad to worse but no appropriate action by the State Government and the Authorities of the U.P. Pollution Control Board is being taken in this regard who are statutorily obliged to check the pollution. We provide that by the next date all appropriate action shall be taken in this regard. Action taken be brought on record before the Court by means of an affidavit."

It has also been noticed in the earlier order that Chief Secretary of the State, who was present before the Court in earlier proceedings, have assured the Court that appropriate action in this regard be taken and brought on the record. As noticed above due to unabated pollution and discharge of untreated water in river Ganges, the colour and quality of the water is deteriorating which become visible at Sangam. No satisfactory compliance in this regard has been brought on record by the State of U.P. The State of U.P. who is to oversee that bodies and persons polluting the water to such great extent which has changed the colour of water be identified and action be taken, has failed to do any substantial work in this regard. An affidavit has been filed by Dr. H.N. Tripathi, learned Counsel appearing for the U.P. Pollution Control Board dated 22.4.2011 sworn by Dr. Rajeev Upadhyay, Chief Environmental Officer, annexing therewith the letters written by Dr. C.S. Bhatt, Member Secretary dated 13.4.2011 to the Director Indian Institute of Toxicological Research, M.G. Marg, Lucknow to carry on indepth study of the causes of occurrence of colour and

water quality. Another letter dated 18.4.2011 of Indian Institute of Toxicology Research has been brought on record indicating concurrence of the institute to carry on desired study. The letter written by the Member Secretary Dr. C.S. Bhatt according to us, is nothing but an act of the U.P. Pollution Control Board abdicating its main function to find out the polluters and take action against them. The U.P. Pollution Control Board, whose main function is to prevent water pollution and take appropriate action against the polluters, instead of taking appropriate action itself, which is a body of experts, is asking the other institution to know the causes of occurrence of colour and water quality. The U.P. Pollution Control Board which has been constituted to check the pollution is not taking any action itself rather it is asking from another institute to know the cause of pollution, whereas the water of river Ganges is decolouring due to unabated pollution, which is continuing from year after year. We are constrained to observe that U.P. Pollution Control Board is not performing its duties as entrusted by statutory provisions. We direct the Chairman of the U.P. Pollution Control Board to file his personal affidavit on the next date and be present in the Court to explain as to what action he has taken in this regard and in compliance of various directions issued by this Court in this petition.

In our order dated 28.3.2011, we have noticed that the State had acquired land for sewage farm in the year 1915 to the extent of 277 acres out of which 45 hectares land had been transferred to Allahabad Development Authority for the purpose of construction of housing colony on the river bank. The proceedings of public Interest Litigation (being PIL No. 54654 of 2009 Re: Sewage Farm) as well as Public Interest Litigation No. 1408 of 2011 were also noticed. This Court has noticed the acute problem of discharge of untreated sewage of Allahabad district directly in river Ganges, which is still

continuing. It was noticed that total capacity of sewage treatment plant functioning at Allahabad is only 93 MLD, whereas sewage generated is 232 MLD hence, 119 MLD untreated sewage is directly thrown in the river Ganges. It was also noticed that the land acquired for the sewage farm had been diverted for the other purpose, which stands admitted in the affidavit of Nagar Nigam, Allahabad. The Chief Secretary, State of U.P. who was present during the earlier proceedings before the Court, had assured the Court that the State shall review the entire issue at its level, with regard to the use of the land which was earlier acquired for the purpose of sewage farm. Today an affidavit of Surya Prakash Misra, Special Secretary, Urban Development sworn on 21.4.2011, has been brought on record annexing the report of the proceedings of the meeting dated 15.4.2011 in the aforesaid regard.

Sri Arun Kumar Gupta, learned amicus curiae has filed an affidavit giving details pertaining to the land of sewage farm which was acquired in 1915 and the diversion of the land for other purposes including transfer of 45 hectares of land by Nagar Nigam, Allahabad for construction of housing colony. Learned Amicus Curiae has also brought on record the Government order dated 31.7.2000 by which the State Government has imposed restriction on constructions within 200 meters from the river bank with the object of saving river Ganges from pollution. Decision was however, taken that relaxation can be granted to Math, Ashram and temple in certain condition. The decision of the Board meeting of the Allahabad Development Authority dated 3.4.2005 has also been brought on record in which a decision was taken that no permission shall be granted for any construction of house within 200 meters of highest flood level of river Ganges. The relaxation for Math etc. was continued. Learned Amicus Curiae has also brought on record the decision of the Committee of Allahabad Development Authority

deciding the objection on master plan 2021 specially the decision of the committee on item No. 45. From decision taken by the Committee at item No. 45, it appears that application was made by the Manager, Sahara India Commercial praying for land use as commercial in Mauja Mavaiya and Mavaiya Devrakh Uperhar Tahsil Karchana on total 133 acres of land. In the decision it has been resolved that upto 200 meters from the river bank, no construction of any kind would be permissible and for next 300 meters constructions can be permitted only in special circumstances. The Board refused permission to change the land use as residential. It is useful to quote the decision of the Committee:

"प्राधिकरण बोर्ड के पूर्व बैठक के निर्णय के अनुसार हाइयेस्ट फर्ल्ड लेवल को देखते हुए बंधा रोड का एलाइमेंट होगा। महायोजना में जो बंधा रोड का एलाइमेन्ट दिखाया गया है वो उसकी पुष्टि भी एरीगेशन विभाग से कर लिया जाये तथा शासन के आदेश के अनुसार बंधा रोड के साथ जा नदी तटीय विकास के लिए 200 मी0 तक कोई निर्माण नहीं होगा तथा अगले 300 मी0 में कोई विशेष भू–उपयोग अनुमन्य किए कये हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व महायोजना सीवेज फार्म, ग्रीन बेल्ट एवं फर्ल्ड इफक्टेड एरिया प्रदर्शित था तथा शासनादेश के अनुसार यहां ग्रीन बेल्ट यथावत नदी तटीय विकास के अन्तर्गत रखा गया है उनका अधिकतर स्थल इस क्षेत्र में आता है। उपरोक्त शासनादेशों के आधार पर इस क्षेत्र को आवासीय करना उपयुक्त नहीं होगा। प्राधिकरण बोर्ड इस पर विचार करना चाहे।"

Sri Ashwani Kumar Misra, learned Counsel appearing for the Allahabad Development Authority referring to affidavit filed in support of his application, has submitted that 45 hectares of land was got transferred by the Nagar Nigam, Allahabad in favour of

Allahabad Development Authority on 25.5.2005 for consideration of Rs. 11 crores. He submits that in Public Interest Litigation being writ petition No. 54654 of 2009 in Re: Sewage Farm, a Division Bench of this Court dismissed the Public Interest Litigation with the observation that the land acquired by one public purpose can be very well utilised for another public purpose. He further submits that another writ petition No. (PIL) 1408 of 2011 has been filed restraining the Allahabad Development Authority from constructing New Prayag Avas Yojna as well as the private company which is making construction near the banks of river Ganges, which Public Interest Litigation is pending and counter affidavit has been called. Learned counsel for the Allahabad Development Authority submits that sufficient land is available for construction of sewage treatment plant and transfer of land was rightly made in favour of Allahabad Development Authority. The judgment and order dated 26.5.2010 in writ petition No. 54654 of 2009 has been referred to and relied.

Learned Counsel for the Allahabad Development Authority has prayed that the order dated 28.3.2011 imposing restriction on construction within 500 meters from mid stream of the river be withdrawn and Allahabad Development Authority be permitted to proceed with its project of constructing a housing colony on the river bank of Yamuna near Sangam in city of Allahabad.

The pollution in the river water of Ganges has arisen to an alarming situation. The apex Court in in M.C. Mehta case reported in (1987) 4 Supreme Court Cases 463 had taken very serious note of the pollution in river Ganges. Following observations were made by the apex Court.

> *"It is the popular belief that the river Ganga is the purifier of all but we are now led to the situation*

that action has to be taken to prevent the pollution of the water of the river Ganga since we have reached a stage that any further pollution of the river water is likely to lead to a catastrophe. There are today large towns inhabited by millions of people on the banks of the river Ganga. There are also large industries on its banks. Sewage of the towns and cities on the banks of the river and the trade effluents of the factories and other industries are continuously being discharged into the river. It is the complaint of the petitioner that neither the government nor the people are giving adequate attention to stop the pollution of the river Ganga. Steps have, therefore, to be taken for the purpose of protecting the cleanliness of the stream in the river Ganga, which is in fact the life sustainer of a large part of the northern India."

In the affidavit filed by Allahabad Development Authority dated 21.4.2011, the Allahabad Development Authority itself has brought on record the affidavit of Nagar Nigam, Allahabad which gives the fact regarding the situation of river pollution in river Ganges. The affidavit of Nagar Nigam sworn by Shiv Lakhan Yadav, Legal Advisor, Nagar Nigam Allahabad filed in PIL No. 54654 of 2009 notices that there are 57 Nalas open drain which are discharging untreated water in river Ganges and Yamuna. It has also noticed that total capacity of treatment plant in Allahabad is only 89 MLD and total untreated discharge is 228 MLD. According to admission of Nagar Nigam itself 120 MLD untreated is being discharged in river Ganges and 108 MLD untreated is discharged in river Yamuna. Following was stated in paragraphs 6,7 and 8:

" 6. That as per detail Number of Nalas are 57 (44 are discharging in Ganga river and 13 are discharging in Yamuna river), total discharge of Untreated water is 228 MLD (120 MLD in Ganga river and 108 MLD in Yamuna river) and capacity of treatment plants is 89 MLD (60 MLD Naini and 29 MLD Salory).

7. That at present out of 228 MLD of untreated discharge water only 89 MLD is being treated as stated above. However schemes of 5 treatment plant has been sanctioned amounting to 355.98 Crores which will treat 60 MLD of untreated water. Under JAICA aided scheme Numayadahi capacity 50 MLD, Kodra capacity 25 MLD, Pongat capacity 10 MLD and Naini capacity 20 MLD amounting 336.07 Crores had been submitted to State Government for submission to Government of India.

8. That as it has ben demonstrated that the total untreated sewage discharge will be covered by different treatment plants to be commissioned at different places by 2013, the land transferred to Allahabad Development Authority is not required for sewage farming, as was previously done before 1985."

The said figures have been given on the basis of the report of the year 2009. No further sewage treatment plant or any other mechanism has been generated. Untreated water is constantly and regularly discharged in river Ganges and Yamuna. The apex Court

in **M.C. Mehta Vs. Union of India,** reported in (1988) 1 Supreme Court Cases 471 held that all municipal Boards which have jurisdiction over the areas through which the river Ganga flows have to take effective steps for undertaking different works in sewerage system. It is useful to quote the directions issued in the aforesaid case in paragraphs 17 and 26.

> " ***17.*** *It is no doubt true that the construction of certain works has been undertaken under the Ganga Action Plan at Kanpur in order to improve the sewerage system and to prevent pollution of the water in the river Ganga. But as we see from the affidavit filed on behalf of the authorities concerned in this case the works are going on at a snail's pace. We find from the affidavits filed on behalf of the Kanpur Nagar Mahapalika that certain target dates have been fixed for the completion of the works already undertaken. We expect the authorities concerned to complete those works within the target dates mentioned in the counter-affidavit and not to delay the completion of the works beyond those dates. It is, however, noticed that the Kanpur Nagar Mahapalika has not yet submitted its proposals for Sewage treatment works to the State Board constituted under the Water Act. The Kanpur Nagar Maha;alika should submit its proposals to the State Board within six months from today.*
>
> ***26.*** *What we have stated above applies mutatis mutandis to all other Mahapalikas and Municipalities which have jurisdiction over the*

areas through which the river Ganga flows. Copies of this judgment shall be sent to all such Nagar Mahapalikas and Municipalities."

277 acres of land was acquired in the year 1915 and 1941 for sewage farm. Nagar Nigam, Allahabad, which was under obligation to utilise the land for the purpose of treating the untreated water have failed to perform its duty. Nagar Nigam has very conveniently in 2005 transferred 45 hectares of land to Allahabad Development Authority and Allahabad Development Authority has decided to construct a housing colony on 45 hectares of land situated on the river bank of Yamuna near Sangam (Where Ganga and Yamuna meet). As noticed above in the PIL writ petition No. 54654 of 2009, this Court has passed the order dated 26.5.2010. In the aforesaid writ petition, the Division Bench noticed the issue involved to the following effect:

> *"The only question involved in this case is as to whether the land, which has been acquired for one public purpose, can be converted for another public purpose or not."*

The Division Bench noticed that out of the total land only 45 hectares of land has been given for the purpose of housing colony, whereas the entire land was originally acquired for the purpose of sledge farm. The Division Bench made following observations:

> *"Factually, learned counsel for the Allahabad Development Authority has come forward with a case that out of the total land, only 45 hectare land has been given for the purpose of housing colony though the entire land was originally*

acquired for the purpose of sledge farm. According to him, the mechanism between such period and the present period has changed. The modern equipments do not require so much land for the purpose, for which the same was acquired and, accordingly, the land in excess of 45 hectares can be utilised for the same. We do not find any logic standing in the way of process of public purpose if no hindrance is being caused to the original public purpose, particularly when we find that all the governmental authorities, being Allahabad Development Authority, Nagar Nigam, Jal Nigam and Environment Department are present before us and nobody is standing in the way but the Court suo motu has taken cognizance in the matter on the earlier occasion. The issue raised in the form of public interest litigation, on which suo motu cognizance has been taken, stands resolved."

From the above judgment of the Division Bench, it appears that Division Bench in the said judgment held that the land in excess of 45 hectares can be utilised for the purpose for which it was acquired. It was not brought before the Division Bench that prior to transfer of 45 hectares of land, the large portion of the area was already transferred for other purposes which has been detailed in the affidavit of Nagar Nigam. The Division Bench passed the order on the premise that rest of the land except 45 hectares, is still available for sewage farm. We however, in this petition cannot take any decision contrary to that which was taken by the Division Bench on 26.5.2010 nor in this writ petition we can entertain any issue regarding transfer of 45 hectares of land to the Allahabad Development Authority by Nagar Nigam. But the question as to

what measures should be taken for checking the pollution in river Ganges is the main subject of present writ petition. In that regard we can proceed to examine and take appropriate measures so that river Ganges may not be further polluted. It is also relevant to refer to the decision of the State Government taken in the meeting dated 15.4.2011 as referred above. From the aforesaid proceedings dated 15.4.2011, it appears that 13.88 hectares of land which was given for fish farm be asked to be returned from Fisheries Department. It was also observed that for extension capacity of sewage treatment plant, land is available.

Learned amicus curiae has also pointed out that another decision has been taken by administration to construct the housing colony in the locality Ganga Nagar on the bank of river Ganga.

Ganges plain in the northern India has been always treated to be most fertile area. Due to increase of population enormous and unregulated and unplanned constructions have begun on both sides of river Ganges, which is continuous and unabated process. It has been noticed that in highest flood of 1978, large number of villages on the bank of river Ganges had submerged. Learned Amicus Curiae has brought on the record a booklet issued by the District Administration Allahabad 'Badh Prabandh Yojna 2011-2012' in which flood affected villages have been mentioned and the villages Jahangirabad and Mavaiya, where the sewage farm land is situate have been included in the villages which are affected by Ganga flood.

Unabated and enormous construction on the river bank is also one of the source of increasing pollution in river water and a source for throwing untreated sewage dirt in the river with no mechanism to check. As noticed above, Allahabad Development Authority while rejecting the application of Sahara Commercial Corporation for permitting the change of land use as residential in

villages mentioned therein, recorded that within 200 meters from highest flood level, construction is wholly prohibited and within next 300 meters permission be granted only in special circumstances. Restriction in making construction of housing colony within 500 meters of highest flood level of river is necessary and mandatory to check the further pollution which may be caused by such housing colonies. We have noticed that in spite of repeated directions, neither the Nagar Nigam nor the State of U.P. has been able to come with any measure to check release of untreated sewage in river Ganges. 134 MLD untreated sewage, according to own case of Nagar Nigam is being discharged in river Ganges daily and according to the respondent new sewage treatment plant of the capacity 60 MLD shall be commissioned by 2013. New sewage treatment plant which has been mentioned and proposed has yet not started and we have reasonable doubt as to whether it will be able to function by 2013. Stopping construction up to 500 meters from highest flood level on the banks of both the rivers Ganges and also on the part of river Yamuna adjoining Sangam has to be directed in the city of Allahabad. The earlier order dated 28.3.2011 however requires modification.

We thus direct that no construction shall be undertaken by the Allahabad Development authority or by any private builders within 500 meters of highest flood level of river Ganges in city of Allahabad as well as part of river Yamuna adjoining the river Ganges (Sangam). The Allahabad Development Authority and the district administration shall ensure that no construction be made in the aforesaid area. We however, give liberty to any aggrieved person to make appropriate application in this petition with regard to above restrictions, if he feels so aggrieved.

Sri Rajeev Lochan Shukla, learned counsel appearing for the tanneries has submitted that a date be also fixed for considering

the tanneries matter. We fix 20.5.2011 for consideration of tanneries matter.

As agreed by learned counsel for the parties,next date in the present case is fixed as 13.5.2011 at 2 p.m.

Learned Special Counsel appearing for the State as well as learned Additional Advocate General referring to the affidavit has submitted that detail timetable is being given for repair of the roads which were dug during the laying down of the sewer line. Learned Amicus Curiae as well as other counsels have submitted that there is no proper repairing of the roads and pits are lying on the road unattended by the authorities. Although in earlier affidavit, it was stated that repairing of the road shall be completed by February, 2011 but according to the own case of the respondents, the repairing of the road has not yet been started. We are of the view that authorities of U.P. Jal Nigam, who is executing agency for laying down the sewer, and the P.W.D. are slack and are not making proper supervision which they are expected with regard to repairing of the road. We direct all the authorities including the authorities of U.P. Jal Nigam and P.W.D. to take appropriate steps regarding restoration of the roads in city of Allahabad, which were got dug during the laying of the sewer line. Appropriate affidavit in this regard be filed by U.P. Jal Nigam, P.W.D. as well as State of U.P. by the next date.

Order Date :- 22.4.2011

LA/-

संलग्नक:- (10)

(4)

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

प्रेषक,

सं0स0/प्र0अ0–हाईटेक,
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।

सेवा में,

श्री अजय मिश्र,
अधि0 हस्ताक्षरी,
मे0 पंचम रियलकान प्रा0लि0
एन/ए/2, द्वितीय तल, सिविल स्टेशन, ताशकन्द मार्ग,
इलाहाबाद।

पत्रांक: 67/हा0टे0से0/वि0प्रा0/2011 दिनॉक: मई 02, 2011

विषयः– मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः 4003/2006 रिःगंगा पाल्यूशन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा दिनॉक 22–4–2011 को पारित आदेशें के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या– 62/हा0टे0से0/वि0प्रा0/2011 दिनॉक 18–4–2011 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उपर्युक्त के क्रम में पुनः अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा संदर्भित रिट याचिका की अग्रेतर सुनवाई करते हुए दिनॉक 22–4–2011 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैं:–

"We thus direct that no construction shall be undertaken by the Allahabad Development Authority or by any private builders within 500 meters of highest flood level of river Ganges in city of Allahabad as well as part of river Yamuna adjoining the river Ganges (Sangam). The Allahabad Development Authority and the district administration shall ensure that no construction be made in the aforesaid area. We however, give liberty to any aggrieved person to make appropriate application in this petition with regard to above restrictions, if he feels so aggrieved."

जैसा कि आपको पूर्व में ही उपर्युक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है, मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश निजी विकासकर्ताओं पर भी बाध्यकारी प्रभाव रखते हैं। अतः आपको पुनः सूचित किया जाता है कि आप मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनॉक 22–4–2011 (छायाप्रति संलग्न) को दिये गये उपर्युक्त आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए स्थल पर कार्य तत्काल रोक दें। यदि आप चाहें तो संदर्भित याचिका में पक्षकार बन कर प्रार्थनापत्र/शपथपत्र के माध्यम से मा0 न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है।

उक्त के संबंध में आप द्वारा प्रेषित पत्र संख्या–आर0ई0पी0एल0/इला0/हाई–टेक टा0/564 दिनॉक 26–4–2011 मा0 उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेशों के परिप्रेक्ष्य में एतद्द्वारा निक्षेपित किया जाता है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
3.5.2011
(सीमा सिंह)
सं0स0/प्र0अ0–हाईटेक

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग (गंगा सेल), उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
2– मे0 पंचम रियलकान प्रा0लि0, रजिस्टर्ड आफिस–10, लोकल शापिंग सेन्टर, कालका जी, नई दिल्ली–110019 को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।

(सीमा सिंह)
सं0स0/प्र0अ0–हाईटेक
इ0वि0प्रा0, इलाहाबाद।

284 ~~168~~ 91.

~~311~~

①

308

Amar Ujala - 07/05/11 - cm 1ag0x10. 6

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

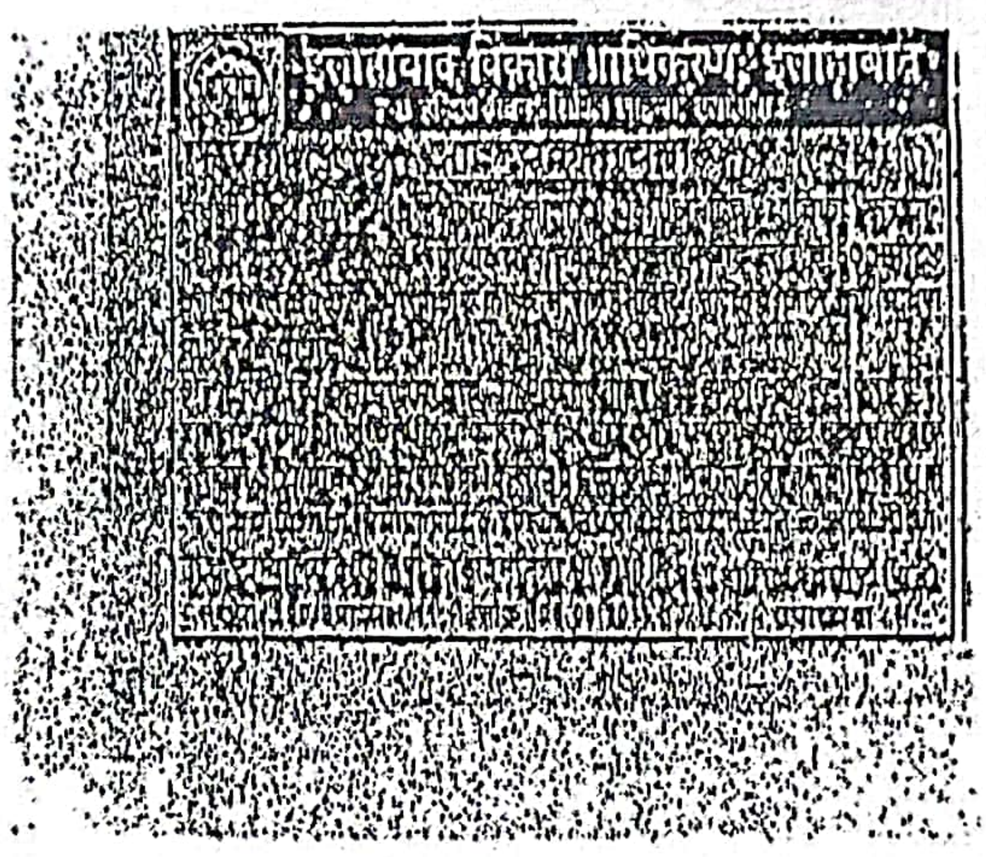

OMAXE
ning dreams into reality

OMAXE WATERFRONT
Hi-Tech City, Allahabad

Ref. No. REPL/Alld./Hi-Tech/571

Dated : 07.05.2011

To,

Seema Singh
Joint Secretary
Allahabad Development Authority,
Allahabad.

Kindly take reference of your letter dated 03.05.2011 numbered as 67/हा0टे0से0/वि0प्रा0/2011 on regarding the order dated 22.04.2011 passed by Hon'ble High Court in Civil Misc. Writ Petition No. 4003 of 2006 (Ref : Ganga Pollution Vs. State of U.P. and others).

With reference to the aforenoted letter, it is submitted that M/s Pancham Realcon Pvt. Ltd. is carrying its operation in pursuance to the Memorandum of Understanding executed with Allahabad Development Authority.

A bare perusal of the following terms of the MoU would establish that the company is committed to:

(i) Establish the Hi-tech Township is an extremely public oriented and environmental friendly project. Special care has been taken to ensure that all the forms of the Environmental Laws shall be followed and in this regard all the clearances from the relevant departments and the authorities of the Environmental Department have already been taken.

(ii) It is noteworthy that the township is being ensured to be kept as a zero discharge zone. To keep Ganges free from

pollution is a commitment of the project as it has been a pronounced policy of the company itself.

However, it appears that due to misconception or mis-projection of the Amicus Curie the following facts have not been appropriately projected before the Hon'ble High Court while the order dated 22.04.2011 was passed.

a. Section 57 of U.P. Urban Planning & Development Act, 1973 (hereinafter referred as Act of 1973) empowers the Development Authority to make byelaws consistent with the aforenoted Act and the Rules made thereunder with a previous approval of the State Government for carrying out the purpose of Act. 1973.

b. In pursuance thereto, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 was made as byelaw of the Allahabad Development Authority.

c. Clause 03.01.10 of the aforenoted byelaw, which relates to the issue in question is reproduced hereunder:

गंगा नदी के किनारे 200 मीटर क्षेत्र में निर्माण अनुज्ञा–

1. गंगा नदी के किनारे बसे नगरों में नदी तट से 200 मीटरक्षेत्र में केवल विद्यमान भवनों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार तथा हेरिटेज भवनों के सम्बन्ध में 'इंटैक' के परामर्श से संरक्षण कार्य अनुमन्य होगें, शेष गतिविधियां निषिद्ध होंगी।
2. गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख तीर्थ स्थलों पर नदी तट से 200 मीटर के क्षेत्र के अन्तर्गत मठ, आश्रम तथा मंदिर का निर्माण निम्नलिखित शर्तो के अधीन अनुमन्य होगा :

(क) भू–आच्छादन 35 प्रतिशत तथा एफ.ए.आर. 1.5 अनुमन्य होगा।

(ख) प्रस्तावित निर्माण के साथ एक योजना प्रस्तुत की जाएगी जिसमें यह सुनिश्चित हो कि नदी में प्रदूषण नहीं होगा। योजना जल निगम/जल संस्थान अथवा विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकार पाये जाने पर नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत किया जाएगा।

(ग) ड्रेनेज सीधे नदी में अवमुक्त नहीं किया जाएगा, बल्कि अन्य नालों, आदि में ले जाने की व्यवस्था की जाएगी।

(घ) यदि क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था नहीं है, तो निवास स्थान/धर्मशाला, आदि अनुमन्य नहीं होंगी।

d. From the above, it is clear that as per the existing byelaws, the restrictive limit for construction from the bank of river is 200 meters.

e. It is noteworthy the Master Plan-2021 was finalized in the year 2006 after completion of the procedure provided under Section 8,10,11 and 12 of the Act of 1973 after affording due opportunity of being heard under Section 11 of the Act. of 1973. The said Master Plan is final, unlamented un-assailed and has not been modified or quashed by any authority or court.

f. After finalization of the Master Plan-2021 in pursuance to the aforesaid exercise, the final resolution was passed and notified vide Government Order No. 124/CM-9-3-2000-127 Comp/99 dated 31st July, 2000 after its adoption under Item No. 5 of Development Authority meeting of 1983 vide Sankalp No. 1337 dated 03.04.2005.

g. The Zoning Regulation has been detailed in the Master Plan 2021 on page 125. Chapter of the said Master Plan reads as under:

v गंगा यमुना नदी के दोनों ओर हरित पट्टिका :

शासनादेश संख्या–124/सीएम/9–आ–3–2000–27 कैम्प/99 दिनांक 31 जुलाई 2000 के अनुसार गंगा यमुना नदी के किनारे से 200 मी0 की गहराई तक धार्मिक मान्यताओं से जुड़े हुये प्रमुख मठ, आश्रम एवं मन्दिर आदि के निर्माण की अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अन्तर्गत प्रदान की जा सकती है।

1. इस क्षेत्र में भू–आच्छादन 35 प्रतिशत तथा एफ0ए0आर0 1.5 होगा, जैसा कि सार्वजनिक सुविधाओं के अनुरूप अनुमन्य हो। किसी भी भूखण्ड का क्षेत्रफल एक एकड़ से कम नहीं होगा।
2. आवेदक को भवन मानचित्र के साथ एक योजना प्रस्तुत करनी होंगी जिसमें यह सुनिश्चित हो कि इससे नदी का जल प्रदूषित नहीं होगा। इसके लिए सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा।
3. ड्रेनेज सीधा नदी में अवमुक्त नहीं किया जायेगा अपितु इसे अन्य नालों या सीवेज से मिलाने की व्यवस्था करनी होगी।
4. यदि क्षेत्र में सीवेज व्यवस्था नही है तो अपने स्रोतों से सेप्टिक टैंक बनाना होगा ताकि मल नदी में न जाने पाये।
5. यह योजना जलनिगम/जल संस्थान अथवा विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की जायेगी तथा स्वीकृति के पूर्व समिति का अनुमोदन लेना होगा।
6. वर्तमान अभिलेखों के अनुसार इस क्षेत्र में ग्रामीण आबादी यथावत बनी रहेगी, जिसके लिए विकास प्राधिकरण को लाल–डोरी क्षेत्र निर्धारित करना होगा तथा उस सीमा में ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत रहने वालों लोगों को आवासीय भवन निर्मित करने की अनुमति उस ग्राम में विगत 10 वर्षो से रहने का प्रमाण–पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत करने के उपरान्त ही प्रदान की जाएगी तथा किसी प्रकार का कालोनाईजेशन अनुमन्य नही होगा।

7. हरित पट्टिका के अन्तर्गत विशेष परिस्थितियों में निर्माण/विकास की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में निम्न समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

1. आयुक्त/अध्यक्ष, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद या उनके द्वारा नामित अधिकारी
2. जिला अधिकारी, इलाहाबाद या उनके द्वारा नामित/अधिकारी
3. उपाध्यक्ष, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद
4. सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजना विभाग उ0प्र0, इलाहाबाद।
5. मेलाधिकारी, कुम्भ मेला, इलाहाबाद।

h. In view of above, it is absolutely clear that as per duly notified resolution dated 31.07.2000, which is the part of the Master Plan 2021, the restrictive limit for construction from the bank of river Ganga and Yamuna has been fixed to be 200 meters . All the claims to the contrary are apparently in consistent with:

i. the existing byelaws:

j. against the existing Master Plan, which had been finalized in pursuance to the complete exercise provided under the aforenoted Act.

It is made clear that our company is proceeding strictly in accordance with:

a. All the Environmental Regulations and Laws having secured all the clearance certificates from the relevant authorities:

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद।

प्रेषक,

जोनल अधिकारी,
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।

सेवा में,

श्री अजय मिश्र,
अधिकृत हस्ताक्षरी,
मेसर्स पंचम रियलकॉन प्रा0लि0,
एन/ए/2 द्वितीय तल, सिविल स्टेशन, ताशकन्द मार्ग,
इलाहाबाद।

पत्रांक :– [illegible] दिनांक 02/07/2011

विषय :– मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.03.2011 एवं 22.04.2011 नदी के उच्चतम जल स्तर से 500 मीटर की दूरी पर निर्माण के रोक के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.03.2011 एवं 22.04.2011 को दिये गये आदेश का उद्धरण अंकित करते हुए इस कार्यालय के पत्र दिनांक 18.04.2011 एवं दिनांक 03.05.2011 को हाईटेक टाउनशिप के निर्माण के सम्बन्ध मे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने हेतु सूचित किया गया था, लेकिन निरीक्षण दिनांक 17.06.2011 को पाया गया कि आप द्वारा तीन कमरो पर छत डालने का कार्य कराया जा रहा था जो कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेशो का उल्लंघन है, जिसे मौके पर प्राधिकरण द्वारा बन्द भी कराया गया है। अतः आपके इस कृत से भविष्य मे अवमानना की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

अतः आपको पुनः सूचित किया जाता है कि मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए संगम क्षेत्र (गंगा/यमुना नदी) के उच्चतम जल स्तर से 500 मीटर की दूरी तक किसी प्रकार का निर्माण न कराये, अन्यथा उक्त के लिये आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगे।

भवदीय,

जोनल अधिकारी,
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।

प्रतिलिपि :– हाईटेक सेल इ0वि0प्रा0 इलाहाबाद को सूचनार्थ।

जोनल अधिकारी,

अति महत्वपूर्ण/मा0 उच्च न्यायालय प्रकरण

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

प्रेषक,

सं0स0/प्र0अ0–हाईटेक,
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।

सेवा में,

श्री अजय मिश्र,
अधि0 हस्ताक्षरी,
मे0 पंचम रियलकान प्रा0लि0
एन/ए/2, द्वितीय तल, सिविल स्टेशन, ताशकन्द मार्ग,
इलाहाबाद।

पत्रांकः 71 /हा0टे0से0/वि0प्रा0/2011 दिनॉकः जुलाई 22, 2011

विषयः– मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः 4003/2006 रि:गंगा पाल्यूशन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा दिनॉक 22–4–2011 को पारित आदेशें के अनुपालन के संबंध में।

———

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या– 62/हा0टे0से0/वि0प्रा0/2011 दिनॉक 18–4–2011 एवं पत्र सं0–67/हा0टे0से0/वि0प्रा0/2011 दिनॉक 3–5–2011 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा संदर्भित रिट याचिका की अग्रेतर सुनवाई करते हुए दिनॉक 22–4–2011 को पारित निम्नलिखित आदेशों से आपको अवगत कराया गया थाः–

"We thus direct that no construction shall be undertaken by the Allahabad Development Authority or by any private builders within 500 meters of highest flood level of river Ganges in city of Allahabad as well as part of river Yamuna adjoining the river Ganges (Sangam). The Allahabad Development Authority and the district administration shall ensure that no construction be made in the aforesaid area. We however, give liberty to any aggrieved person to make appropriate application in this petition with regard to above restrictions, if he feels so aggrieved."

जैसा कि आपको पूर्व में ही अवगत कराया जा चुका है मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश निजी विकासकर्ताओं पर भी बाध्यकारी प्रभाव रखते हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में इस कार्यालय के संदर्भित पत्रों द्वारा आपको निर्देशित किया गया था आप मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनॉक 22–4–2011 को दिये गये उपर्युक्त आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए स्थल पर कार्य तत्काल रोक दें तथा यदि आप चाहें तो संदर्भित याचिका में पक्षकार बन कर प्रार्थनापत्र/शपथपत्र के माध्यम से मा0 न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है। इसी क्रम में आप द्वारा प्रेषित पत्र संख्या–आर0ई0पी0एल0/इला0/हाई–टेक टा0/564 दिनॉक 26–4–2011 मा0 उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेशों के परिप्रेक्ष्य में निक्षेपित करते हुए अवगत कराया जा चुका है।

इस संबंध में अग्रेतर अवगत कराना है कि उक्त जनहित याचिका में मा0 उच्च न्यायालय की ओर से श्री अरूण कुमार गुप्ता को एमीकस क्यूरी नियुक्त किया गया है। एमीकस क्यूरी श्री गुप्ता द्वारा दिनॉक 8–7–2011 को उक्त जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान् दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्स में दिनॉक 10–6–2011 को प्रकाशित समाचार एवं फोटोग्राफ की प्रति (छायाप्रति संलग्न) के साथ मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष यह एप्लीकेशन दाखिल की गयी है कि आपके (मे0 पंचम रियलकान प्रा0लि0, ओमेक्स) द्वारा 'ओमेक्स वाटर फ्रन्ट सिटी' में निर्माण कार्य मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के बावजूद किया जा रहा है। उक्त स्थिति अत्यन्त खेदजनक है और यह मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है। अगली सुनवाई की तिथि 26–7–2011 नियत है।

अतः आपको एतद्द्वारा पुनः निर्देशित किया जाता है कि मा0 उच्च न्यायालय के संदर्भित आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें तथा स्थल पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें। इस कार्यालय द्वारा स्पष्ट रूप से संसूचित किये जाने के उपरान्त भी स्थल पर हुए किसी भी प्रकार के निर्माण के लिए आप स्वतः उत्तरदायी है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीया,

22/7/2011

(सीमा सिंह)
सं0स0/प्र0अ0–हाईटेक

on the death of Husain. "He himself was one of the master pieces by the Almighty and his loss is irreparable," said Bhowmick.

Thursday, Anupam ... previously participated in many programmes in Allahabad, Lucknow, and Varanasi.

HTC

Sridip Pal of Lady Brabourne College, Kolkata.

"The participants were national topper of the NGPE

Deputy registrar (academics), Allahabad University (AU) has informed that the viva-voce

from Ilan... for subm... June 25.

Hindustan Times dt 10/6/11

'Construction on Ganga flood plains must stop'

Kenneth John

kenneth.john@hindustantimes.com

ALLAHABAD: Noted water conservationist and member of National Ganga River Basin Authority (NGRBA) Rajendra Singh inspected ongoing construction of Omaxe water front city on the flood plains of the Ganga here on Thursday.

The Magasaysay awardee, also known as *'Jal Purush'*, was accompanied by senior advocate and amicus curie appointed by Allahabad high court in Ganga pollution matter Arun Kumar Gupta.

Talking to *Hindustan Times*, Rajendra Singh expressed resentment over allocation of flood plains for construction work. "I will hold a meeting with the chief secretary, Uttar Pradesh on Friday in Lucknow and in any case the township cannot be allowed to come up on flood plains. The NGRBA's prime objective is to protect the *flood plains for which things will now have to be taken up at higher level*," he added.

Hindustan Times had reported the matter in its issue dated March 20. On a PIL filed by Ganga Mahasabha, the court had ordered a ban on construction within 500 metres of the highest flood level (HFL) near Ganga river on April 22.

However, Gupta informed that the construction continued unabated. "The court once again directed the district administration and ADA to stop the construction work and apprise the court in the next hearing on July 8. However, during inspection it was found that the construction was going on, which itself amounted to contempt of court," he added.

Omaxe had rportedly not procured the mandatory 'pre-environmental clearance' from the ministry of environment and forest as required in clause number 24 of the memorandum of understanding signed by ADA and Omaxe India Limited.

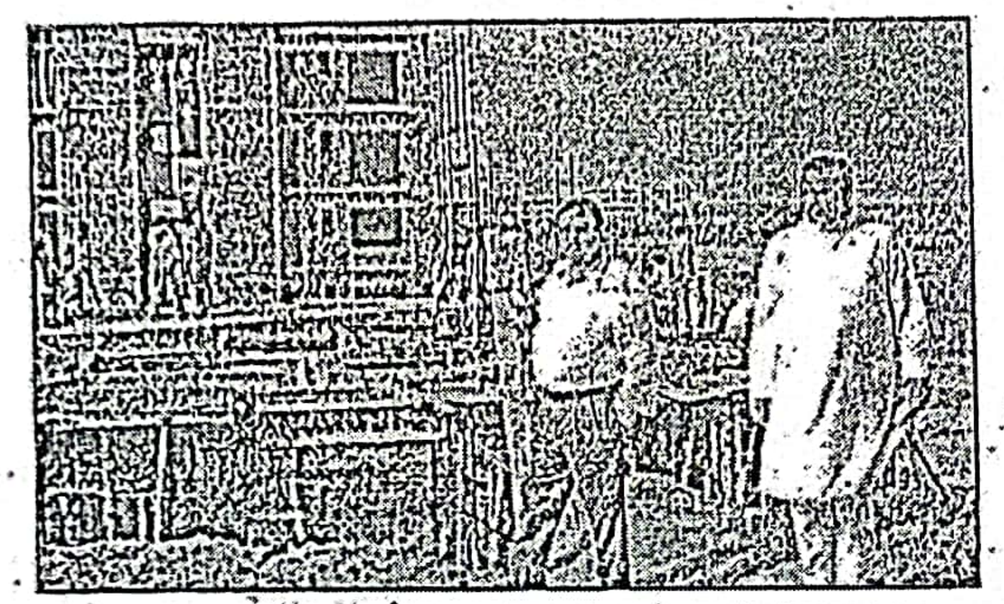

■ Jal Purush Rajendra Singh (in white pyjama kurta) along with Amicus Curie Arun Kumar Gupta looking at the ongoing construction work at Omaxe waterfront city. HT PHOTO

DM INSPECTS SANGAM AREA

ALLAHABAD: District magistrate Alok Kumar inspected the Sangam area and assessed the cleanliness in the area here on Thursday. He along with Magsaysay award winner 'Jal Purush' Rajendra Singh discussed at length the strategy for launching a campaign for cleaning the Sangam area.

Singh apprised the DM about the threat to aquatic flora of the rivers posed by the weed water hyacinth.

The DM immediately ordered deployment of about a hundred labourers along with various non-government organisations for getting the river free of the weed by June 11.

The DM directed the Nagar Nigam officials to ensure that the waste cleaned from the river was not dumped on the Sangam banks but was instead were put in garbage bins kept for waste disposal. HTC

(4)

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

प्रेषक,

उपाध्यक्ष,
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।

सेवा में,

श्री अजय मिश्र,
अधि0 हस्ताक्षरी,
मे0 पंचम रियलकॉन प्रा0लि0
एन/ए/2, द्वितीयतल, सिविल स्टेशन,
ताशकन्द मार्ग, इलाहाबाद।

पत्रांक: 436 /उपाध्यक्ष/2011 दिनांक: अगस्त 19 ,2011

विषयः मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन जनहित याचिका संख्याः 4003/2006 रिःगंगा पाल्युशन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

जनहित याचिका संख्या 4003/2006 रिः गंगा पाल्युशन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा इस तथ्य का संज्ञान लिया गया है कि मा0 न्यायालय के निषेधाज्ञा के बाद भी आप द्वारा हाईटेक टाउनशिप के अन्दर निर्माण कार्य जारी रखा गया है और इसे बन्द नहीं किया गया है । मा0 न्यायालय द्वारा इसे अत्यन्त प्रतिकूल दृष्टि से देखा गया है और न्यायालय की खुली अवमानना के रूप में अवधारित किया गया है । मा0 न्यायालय के आदेशों के कम में इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा भी आपको इस आशय के स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि नदी के किनारे बाढ़ के उच्चतम स्तर के 500 मीटर की दूरी तक निर्माण एवं विकास कार्य कदापि न कराया जाये परन्तु आप द्वारा इन निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है

एतद्द्वारा पुनः आपको यह आदेश दिये जाते हैं कि मा0 उच्च न्यायालय में याचिका की सुनवाई लम्बित रहने तथा इस संबंध में अन्तिम आदेश पारित होने तक टाउनशिप के अन्तर्गत समस्त निर्माण एवं विकास कार्य तत्काल प्रभाव से रोक दें और इस आशय की लिखित सूचना प्राधिकरण कार्यालय को उपलब्ध करायें । ऐसा न करने की दशा में आदेशों की अवहेलना के दुष्परिणामों के आप स्वयं जिम्मेदार होंगे । निर्माण होता हुआ पाये जाने की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा निर्माणों को ध्वस्त करने की भी कार्यवाही की जायगी।

भवदीय,

19.8.2011

(अनिल कुमार सिंह)
उपाध्यक्ष।

प्रतिलिपि श्री हरीश चन्द्रा, जोनल अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ तकनीकी प्रवर्तन स्टाफ के साथ हाईटेक टाउनशिप के अन्दर अपना अस्थायी कार्यालय बना लें और यह सुनिश्चित करें कि टाउनशिप के अन्दर किसी प्रकार का निर्माण/विकास कार्य नहीं हो रहा है तथा इस आशय का दैनिक प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें जिससे मा0 न्यायालय को सन्तुष्ट किया जा सके ।

(अनिल कुमार सिंह)
उपाध्यक्ष।

संलग्नक-(II)

Plot/ Flat/ Unit Constructed before Interim Stay dated 22.04.2011 by the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad and No-construction has been carried out after the Interim Stay dated 22.04.2011 by the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad till date:

Project name	Plot/ Flat/ Unit Constructed before Interim Stay dated 22.04.2011 by the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad
Omaxe Sangam City Plot -Sector-1	550 Approx.
Omaxe Sangam City Villa (WF) – Sector- 1	35 (under construction)
Water Front EWS-LIG Homes-Sector-1	90 (under construction)
Omaxe Duplex Villa Allahabad-Sector-1	13 (under construction)

01/07/2025

Tarun Sharma
Dy. General Manager
9711800453

संलग्नक- (12)

Latitude: 25.394404
Longitude: 81.894153
Accuracy: 60.0 m
Time: 01-28-2025 16:08
Note: Photographs in the matter of IA no. 2732024 in OA no.515/2023
Powered by NoteCam

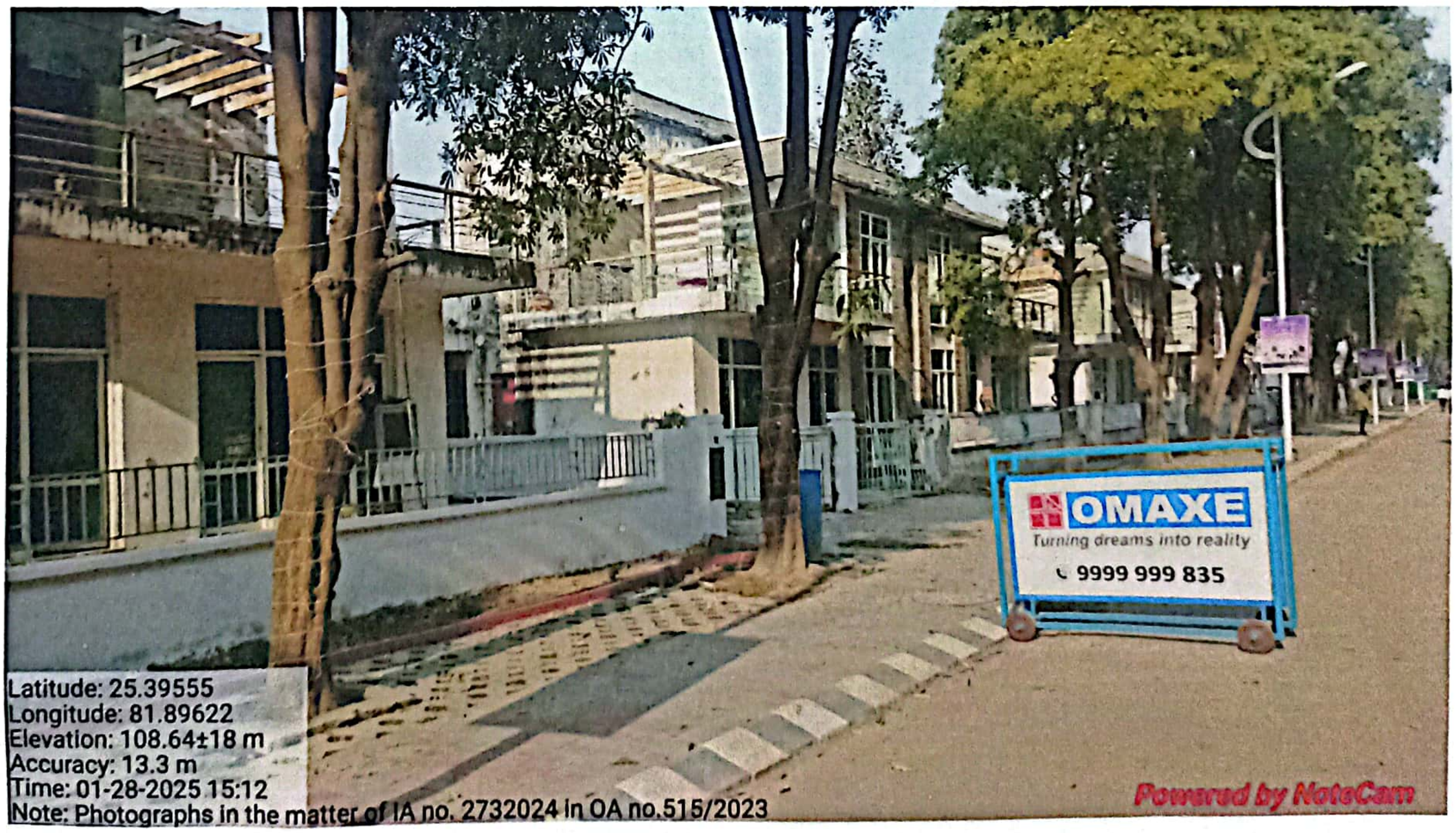
OMAXE
Turning dreams into reality
9999 999 835
Latitude: 25.39555
Longitude: 81.89622
Elevation: 108.64±18 m
Accuracy: 13.3 m
Time: 01-28-2025 15:12
Note: Photographs in the matter of IA no. 2732024 in OA no.515/2023
Powered by NoteCam

संलग्नक - (13)

Latitude: 25.392069
Longitude: 81.898893
Elevation: 103.23±14 m
Accuracy: 5.6 m
Time: 01-28-2025 14:10
Note: Photographs in the matter of IA no. 2732024 in OA no.515/2023
Powered by NoteCam

संलग्नक-(14)

क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

आवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर-10, योजना संख्या-3, झूँसी, प्रयागराज- 211019
Email-roprayagraj@uppcb.in

पत्रांक ७०।५१२ / NGT OA. NO. 515 /2023 / 2025 दिनांक 01/02/2025

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
बाढ़ कार्यखण्ड, सिंचाई विभाग,
प्रयागराज।

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण
अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण

विषयः- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0 515/2023 (इन आई0ए0 नं0 372/2024) गंगा पाल्यूशन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में दिनांक 12.11.2024 को पारित आदेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0 515/2023 (इन आई0ए0 नं0 372/2024) गंगा पाल्यूशन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में दिनांक 12.11.2024 को आदेश पारित किया गया है, जिसके मुख्य अंश निम्नवत् है :-

".....8. IA No. 372/2024 has been filed by Respondent No. 26 seeking a direction permitting it to continue the construction of the project. The reply to the said IA has been filed by the CSIR-NEERI, CPCB, the Prayagraj Development Authority and NMCG. Learned Counsel for the UPPCB submits that he will file the reply to the IA within two weeks 6 positively. It will be open to all other respondents to file reply to the IA within the same period and the Applicant may file the rejoinder, if require, within two weeks thereafter......"

प्रश्नगत प्रकरण में अगली सुनवाई मा0 अधिकरण में दिनांक 11.02.2025 को नियत है। अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण मेसर्स पंचम रियलकॉन प्रा0लि0 (मेसर्स ओमेक्स लिमिटेड), ग्राम-देवरख उपरहार, ग्राम-देवरख उपरहार, देवरख कछार, चक विश्वनाथ, चकतेजुदिशी, मवई उपरहार, मढावन उपरहार एवं लवायनकलां तहसील-करछना, जनपद-प्रयागराज से सम्बन्धित है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में जनपद-प्रयागराज में गंगा नदी के फ्लड प्लेन जोन डिमार्केशन के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही/सूचना 03 दिन के अन्दर इस कार्यालय के ई-मेल roprayagraj@uppcb.in पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

01/2/25

(डॉ0 एस0सी0 शुक्ला)
क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नकः-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. उपाध्यक्ष महोदय, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी 01/2/25

sunil PA-AE/RO. COM

IA No 372 of 2024 In OA No 515 of 2023 Ganga Pollution vs state of U P

From: Pradeep Misra (pradeepmisra@yahoo.com)

To: contactadvsa@gmail.com; bhanwar09jadon@gmail.com; gigicgeorge.adv42@yahoo.in

Date: Wednesday, February 5, 2025 at 11:09 AM GMT+5:30

Sir,

Please find attached the Document

With Regards,

(PRADEEP MISRA)

Ganga pollution IA Reply.pdf
17.2MB